E-mail:-adhuniksamachar2014@gmail.com website:www.adhuniksamachar.com

आधुनिक समाचार

आधुनिक भारत का आधुनिक नजरिया

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वर्ष -12 अंक - 120 प्रयागराज, शनिवार 25 जुलाई, 2026 पृष्ठ- 8 मूल्य : 3.00 रूपये

ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका,बस फैसला लेना बाकी-ट्रम्प, ईरान ने कहा- इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है।' ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। ट्रम्प के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी 'और भारी कीमत' चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। इधर, ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर उसकी सेना देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। इससे पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स-1. सऊदी के दो जहाजों पर हमलाः यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के दो तेल टैंकर एन्सेलिया और लैला पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। संगठन का कहना है कि दोनों जहाजों में आग लग गई। 2. हूती विद्रोहियों के डर से 10 जहाजों ने रास्ता बदलाः बाब अल-मंदेब स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे कम से कम 10 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। अब ये जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर तय कर रहे हैं। 3. ब्रिटेन ने अमेरिका को सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी दीः ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को ब्रिटिश सैन्य अड्डों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया और ग्लॉस्टरशायर का फेयरफोर्ड एयरबेस अमेरिकी विमानों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेंगे। 4. भारत की अब तक 26,000 उड़ानें रद्दः अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण 20 जुलाई तक भारतीय एयरलाइंस को करीब 26 हजार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इसके अलावा कई उड़ानों का रास्ता बदला गया और उनमें देरी भी हुई। 5. ट्रम्प का 95 अरब डॉलर का रक्षा बजट पासः ट्रम्प को ईरान युद्ध के बीच बड़ी राजनीतिक जीत मिली है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 95 अरब डॉलर का रक्षा बजट प्रस्ताव 216-214 वोटों से मंजूर कर दिया।अब इसे मंजूरी के लिए सीनेट में जाएगा। इससे ईरान युद्ध और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा।

नेपाली पीएम बालेन शाह ने अपना ही नियम क्यों तोड़ा! भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे, 3 महीने में ही फैसले से पलटे

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन शाह) पहली बार अपने बनाए नियम से हटकर विदेशी राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया था कि वह किसी भी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बालेन शाह भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। इसे नेपाल की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह अपने दोनों सबसे बड़े पड़ोसियों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखना चाहता है। एक ही दिन दोनों देशों के राजदूतों के साथ मीटिंग-बालेन शाह नहीं चाहते थे कि भारत या चीन में से किसी को यह लगे कि दूसरे देश को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने दोनों देशों के राजदूतों से एक ही दिन अलग-अलग मुलाकात करने का फैसला किया है। दोनों बैठकें एक के बाद एक होंगी, ताकि दोनों देशों के साथ समान व्यवहार का मैसेज जाए। **आगे की खबर पेज संख्या 07 पर..**

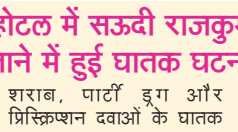

रात 12 बजे पीएम ने छात्रों को दिया वीडियो संदेश पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, 27 जुलाई तक संसद में पेश हो सकता है

नयी दिल्ली। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया

जा सकता है।मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर आज चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर 2.56 मिनट का एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। कहा- 'पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।' उन्होंने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। विभागों ने देर रात मुझे मसौदा भेजा है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान हैं। इस पर शुक्रवार को कैबिनेट के बीच चर्चा होगी। पीएम के वीडियो संदेश पर राहुल ने कहा- प्रधान को हटाएं- राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे आधी रात का बेकार वीडियो बताया। उन्होंने लिखा- मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात के इस बेकार वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को हटाएं, छात्रों को पीटने वालों को सजा दें और माफी मांगें। सीजेपी ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार जो सबसे सख्त कार्रवाई कर सकती है, वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान को हटाना है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा- मोदी जी, कल ही धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। यही सबसे सख्त कार्रवाई है जो आप कर सकते हैं। पीएम ने गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था-पीएम मोदी ने गुरुवार को ही पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी। दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ा है। इसी नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अबतक 13 आरोपी पकड़े गए हैं। सीबीआई जल्द ही इस चार्जशीट फाइल कर सकती है। पिछले 4 दिन में पेपर लीक पर पीएम के 2 बयान-21 जुलाईः पेपर लीक घोर पाप है एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि पेपर लीक घोर पाप है। सरकार को जैसे ही जानकारी मिली, उसने तुरंत कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्यों से भी सहयोग की अपील की ताकि भविष्य में पेपर लीक रोके जा सकें।

अमेरिका ने भारत पर 10फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, 60 देशों पर जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से लागू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) ने फोर्स्ड लेबर (जबरन मजदूरी) से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन देशों पर 10फीसदी से 12.5फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत उन 17 देशों में शामिल है, जिन पर 10फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। वहीं

बाकी 43 देशों पर 12.5फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत की है। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10फीसदी टैरिफ वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने फोर्स्ड लेबर से बने सामान पर प्रतिबंध लगाया है या ऐसा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। भारत के किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।**आगे की खबर पेज संख्या 07 पर..**

पैलेट्स से जख्मी इरशाद से नड्डा बोले-प्रोटेस्ट में क्यों गए, हॉस्पिटल ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी

नई दिल्ली। 25 साल के इरशाद शेख दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। चेहरे और आंख पर जख्म के निशान हैं। गुरुग्राम में नौकरी करने वाले इरशाद 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में गए थे। तभी पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इरशाद ने महसूस किया कि उनकी पीठ जल रही है। सीने, गले और चेहरे पर घाव हैं। उनसे खून टपक रहा था। आरोप है कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने पैलेट गन चलाई, जिससे इरशाद जख्मी हो गए। मैं 23 जुलाई को इरशाद से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। ईएनटी डिपार्टमेंट में उनका इलाज

चल रहा है। डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। कई बार कोशिश करने के बाद मैं इरशाद तक पहुंच गई। उस वक्त डॉक्टर कमरे में मौजूद थे। बातचीत के दौरान इरशाद ने अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि आप मुझे सीधे मैसेज कर दीजिए। फिर फोन पर हमारी बात हुई। इरशाद ने कहा कि मैं उनसे मिलूं। हॉस्पिटल स्टाफ ने इरशाद से मिलने से रोका- मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंची, तो गार्ड और स्टाफ ने मुझे फिर रोक दिया। इरशाद ने दो बार अस्पताल स्टाफ से कहा कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं। इसके बावजूद मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। कहा कि आप बाहर बैठिए।**आगे की खबर पेज संख्या 07 पर..**

सऊदी से परमाणु समझौता करके 24 घंटे में पलटे ट्रम्प, नई शर्त जोड़ दी, बोले- इजराइल से रिश्ते सुधारे सऊदी

न्यूक्लियर डील अटकी

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब दो दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह डील अटक गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि डील तभी आगे बढ़ेगी, जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा। ट्रम्प ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं मिलेगी। बिना बताए डील की घोषणा से ट्रम्प नाराज-वॉशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प इस बात से नाराज थे कि राइट ने उनकी मंजूरी के बिना समझौते की घोषणा कर दी। इसके बाद फॉक्स न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हुई आलोचना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने ऊर्जा विभाग से समझौते की घोषणा टालने को कहा था, लेकिन विभाग ने हस्ताक्षर समारोह भी किया और मीडिया में इसकी जानकारी भी दी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की शर्त शुरू से ही ट्रम्प की नीति का हिस्सा थी। वहीं ऊर्जा विभाग ने किसी भी मतभेद से इनकार किया। ट्रम्प की नई शर्त ने सऊदी को भी चौंकाया-सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प की घोषणा से सऊदी अरब भी हैरान रह गया। समझौते के मसौदे में कुछ शर्तें पूरी होने पर सऊदी अरब को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलने की बात थी, लेकिन ट्रम्प ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। दोनों देशों ने करीब दो दशक पहले परमाणु ऊर्जा सहयोग की पहल की थी। पिछले साल अक्टूबर में

प्रारंभिक सहमति बनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध और कांग्रेस की संभावित आपत्तियों के कारण समझौता महीनों तक अटका रहा। पिछले सप्ताह ऊर्जा विभाग को लगा कि ट्रम्प की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसकी घोषणा कर दी गई। परमाणु एक्सपर्ट्स ने यूरेनियम संवर्धन की अनुमति और आईएईए के अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की गैरमौजूदगी पर चिंता जताई। वहीं समर्थकों का तर्क था कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो चीन या रूस सऊदी अरब में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर सकते हैं। आखिर अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या, जिसे लेकर डील अटक गई? दरअसल, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में अमेरिका की पहल पर हुआ ऐसा समझौता है, जिसके तहत कुछ अरब देशों ने पहली बार इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य किए। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान इसके तहत इजराइल से जुड़ चुके हैं। अब अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी इसी समझौते का हिस्सा बने। ट्रम्प का मानना है कि अगर सऊदी इजराइल से रिश्ते सामान्य करता है, तो पश्चिम एशिया में अमेरिका का रणनीतिक गठजोड़ और मजबूत होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन भी सऊदी परमाणु समझौते को इजराइल से रिश्ते सामान्य करने से जोड़कर आगे बढ़ा रहा था। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और गाजा युद्ध के बाद यह प्रक्रिया रुक गई। सऊदी का कहना है कि फिलिस्तीन के लिए अलग राज्य का रास्ता साफ हुए बिना वह इजराइल से आधिकारिक रिश्ते नहीं बनाएगा। यही वजह है कि अब न्यूक्लियर डील भी इस शर्त पर अटक गई है। तेल के बावजूद सऊदी को परमाणु ऊर्जा की जरूरत क्यों? सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल सऊदी अरब के पास तेल की कोई कमी नहीं है, तो उसे परमाणु ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसकी वजह है विजन-2030। इसके तहत सऊदी अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहता। दरअसल, देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और अभी इसका बड़ा हिस्सा तेल व गैस से पूरा किया जाता है। अगर बिजली परमाणु ऊर्जा से बनने लगेगी, तो तेल और गैस की खपत घटेगी। इससे सऊदी ज्यादा तेल निर्यात कर सकेगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। इसके साथ ही सऊदी सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाकर अपनी ऊर्जा व्यवस्था को भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत और संतुलित बनाना चाहता है। इसी रणनीति के तहत वह लंबे समय से अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग की कोशिश कर रहा है।

भारतीय व्यक्ति की यरुशलम में हत्या, इजराइली संदिग्ध गिरफ्तार

यरुशलम। यरुशलम के कटामोन इलाके में गुरुवार को

40 साल के भारतीय व्यक्ति का शव एक घर में मिला। पुलिस के मुताबिक, शव फर्श पर पड़ा था और उसके आसपास काफी खून था। इजराइल पुलिस ने हत्या के शक में 31 साल के एक इजराइली नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला आपराधिक प्रकृति का लग रहा है। मृतक और संदिग्ध की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। यरुशलम जिला कमांडर अवशालोम पेलेड भी मौके पर पहुंचे और जिला अधिकारियों के साथ स्थिति का आकलन किया।

पेलेड ने शुरुआती आकलन के बाद जांच जारी रखने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक, मृतक 40 साल का भारतीय प्रवासी कामगार था।

लंदन के लग्जरी होटल में सऊदी राजकुमार की मौत,शराब, जांच में 'अनजाने में हुई घातक घटना' का निष्कर्ष

लंदन। सऊदी अरब के 29 वर्षीय राजकुमार अब्दुल्ला बिन

फहद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज बिन जलावी अल सऊद की लंदन के एक लग्जरी होटल में मौत हो गई। ब्रिटेन की कोरोनर कोर्ट में हुई जांच में सामने आया कि उनकी मौत शराब, पार्टी ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के घातक मिश्रण के सेवन से कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। राजकुमार पिछले 19 नवंबर को लंदन के मैरियट होटल, केंसिंग्टन में ठहरे थे। 25 नवंबर को होटल के पांचवीं मंजिल के कमरे के बाथरूम में वे मृत मिले। असिस्टेंट कोरोनर जीन हार्किन ने मौत को 'मिसएडवेंचर' यानी अनजाने में हुई घातक घटना माना। कोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राजकुमार ने आत्महत्या करने की योजना बनाई थी। इनर वेस्ट लंदन कोरोनर कोर्ट में पेश टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार के खून में अल्कोहल का स्तर 222एमएल प्रति 100एमएल था। यह इंग्लैंड में ड्रिंक-ड्राइविंग की कानूनी सीमा से करीब तीन गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ इतना अल्कोहल भी कोमा की स्थिति पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकता था। राजकुमार ने करीब 600 यूरो प्रति रात के किराए वाले होटल में एक सप्ताह ठहरने के लिए चेक-इन किया था। मौत से एक शाम पहले उन्हें होटल के सीसीटीवी में आखिरी बार जिंदा देखा गया। कोर्ट को बताया गया कि राजकुमार को शराब के दुरुपयोग और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर निर्भरता की समस्या थी।

जेफ्री एपस्टीन से जुड़े फ्रांसीसी शख्स डैनियल सियाद घर पर मृत मिले, लीक फाइल्स में 1000 बार नाम आया था

कोलंबस। अमेरिकी अरबपति और दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े फ्रांसीसी मॉडलिंग स्काउट डैनियल सियाद अपने पेरिस स्थित घर में मृत पाए गए हैं। 69 साल के डैनियल सियाद पर फ्रांस में मानव तस्करी और महिलाओं के यौन शोषण में जेफ्री एपस्टीन की मदद करने के आरोपों की जांच चल रही थी।सियाद ने इन आरोपों से

इनकार करते हुए कहा था कि वह जांचकर्ताओं के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सियाद के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें दुष्कर्म के आरोप भी शामिल थे। अमेरिका में सार्वजनिक की गई एपस्टीन फाइलों के 1,000 से ज्यादा दस्तावेजों में डैनियल सियाद का नाम दर्ज है। 2014 में एपस्टीन को भेजे एक मैसेज में सियाद ने महिलाओं की तलाश करने के अपने काम की तुलना मछली पकड़ने से की थी।

उन्होंने लिखा था, 'इस काम में मैं खुद को कभी-कभी मछुआरा महसूस करता हूं। कभी जल्दी सफलता मिल जाती है, कभी एक भी मछली नहीं मिलती।' हालांकि बाद में सियाद का कहना था कि जेफ्री एपस्टीन ने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया।

डीएम ने मुंशीगंज शहीद स्मारक के निर्माणाधीन कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण,स्मारक परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दिए गए निर्देश

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने मुंशीगंज स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक का स्थलीय निरीक्षण कर पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कराए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुंशीगंज शहीद स्मारक जनपद की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थल का विकास भी उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाना चाहिए, ताकि यहां आने वाले नागरिकों एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें तथा शहीदों के प्रति सम्मान की भावना और अधिक सुदृढ़ हो। जिलाधिकारी ने स्मारक परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि विशेष रूप से पाथवे पर उच्च गुणवत्ता की लाइटें लगाई जाएं, जिससे रात्रि के समय भी परिसर सुरक्षित एवं आकर्षक दिखाई दे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार विकसित की जाए कि पूरे परिसर में कहीं भी अंधेरा न रहे। उन्होंने निर्माण

कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि शेष सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण, निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा समयबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कार्य पूर्ण होने तक नियमित रूप से निगरानी की जाए तथा प्रत्येक चरण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का संरक्षण और विकास जनपद की प्राथमिकता है। इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराएं, ताकि आमजन एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।निरीक्षण के दौरान जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सुधीर गिरी, पर्यटन अधिकारी तनुजा यादव सहित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित एवं समग्र विकास के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ करें कार्य-डीएम

नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न,आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए गए निर्देश

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के नगरीय क्षेत्रों के समग्र, सुव्यवस्थित एवं सतत विकास के उद्देश्य से नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निकायों में संचालित विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नगरों का सुव्यवस्थित विकास तभी संभव है, जब सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पशुओं के शवों के उचित एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उपयुक्त भूमि का शीघ्र चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों को होने वाली असुविधाओं से भी राहत मिलेगी। बैठक में नगरीय क्षेत्रों में जर्जर एवं पुराने विद्युत तारों को चरणबद्ध तरीके से बदलने, सड़कों पर पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विद्युत सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने नगर क्षेत्रों में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए उपयुक्त स्थानों पर पार्किंग स्थलों के विकास, प्रमुख मार्गों एवं बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए, साथ ही नियमित अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने बैठक में हर घर नल योजना की प्रगति की भी समीक्षा की एवं निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार तक शुद्ध पेयजल की सुविधा समयबद्ध रूप से पहुंचाई जाए तथा जिन क्षेत्रों में कार्य शेष है, वहां तेजी से कार्य पूर्ण कराया जाए। जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों तथा संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों को स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शत्रोहन सोनकर सहित जनपद की समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने जेल रोड पर किया वृक्षारोपण,वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास का दिया संदेश

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने आज जेल रोड स्थित इंदिरा नगर पावर हाउस के समीप वृक्षारोपण कर जनपद में हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लोक निर्माण विभाग द्वारा जेल रोड में 1.5 कि0मी0 सड़क की दोनों पटरियों पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत छायादार, फलदार व छोटे शोभाकार वृक्षों को रोपित कराया जा रहा है।जिलाधिकारी ने रोपित पौधों का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा एवं समुचित देखभाल सुनिश्चित की जाए, ताकि उनका संरक्षण हो सके और अधिकतम पौधे विकसित होकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी देखरेख और संरक्षण भी उतनी ही गंभीरता से किया जाए। जनपद को अधिक हरित, स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग महिपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

'साथी पोर्टल' से जुड़े बिना नहीं होगा बीज व्यवसाय

बीज उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन एवं विक्रय की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पारदर्शी

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पाण्डेय ने बताया है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की समयबद्ध एवं पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित 'साथी पोर्टल' को बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण, स्टॉक प्रबंधन तथा विक्रय के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग), लखनऊ तथा शासन के निर्देशानुसार अब बीज व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधियां साथी पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी। बीज उत्पादन से लेकर फसल पंजीकरण, क्षेत्र निरीक्षण, बीज स्रोत सत्यापन, नमूना परीक्षण, टैग एवं प्रमाण-पत्र जारी करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपादित होगी।बीज प्रसंस्करण संयंत्रों पर बीज की आवक, प्रसंस्करण, पैकिंग, लॉट निर्माण, नमूना ग्रहण तथा स्टॉक संबंधी सभी प्रविष्टियां साथी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार भौतिक अभिलेख भी सुरक्षित रखे जाएंगे। बीज का स्टॉक स्थानांतरण, विक्रय एवं वापसी केवल साथी पोर्टल के माध्यम से ही मान्य होगी। अपंजीकृत डीलर अथवा वितरक के माध्यम से बीज व्यवसाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद के सभी बीज विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटरों, सहकारी समितियों तथा सरकारी बीज विक्रय केंद्रों का साथी पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होना अनिवार्य है। पोर्टल के माध्यम से किसान स्तर तक प्रत्येक बीज लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, जिससे बीज की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित होगी। यदि पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज नियंत्रण आदेश-1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी बीज उत्पादकों, डीलरों, वितरकों एवं संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि वे 28 जुलाई 2026 तक शीघ्र साथी पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूर्ण कर शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही किसानों से भी आग्रह है कि वे प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज केवल साथी पोर्टल से जुड़े अधिकृत विक्रेताओं से ही क्रय करें, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज के साथ पारदर्शी एवं विश्वसनीय सेवा प्राप्त हो सके।

आधुनिक समाचार
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र
RNI NO:-UPHIN/2015/63398
प्रयागराज से प्रकाशित
'आधुनिक समाचार' आधुनिक भारत की नई आवाज
अंकपत्र, LIC बांड, रजिस्ट्री पेपर, लाइसेंस खो गया, गुमशुदा, नाम, पता, जन्मतिथि परिवर्तन, अन्य कामर्शियल विज्ञापन उचित दर पर छपवाने के लिए सम्पर्क करें। +91 79914 85344

उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की मा0 उपाध्यक्ष ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सीएचसी हरचन्दपुर व बालिका गृह का किया निरीक्षण

मा0 उपाध्यक्ष ने जिला पंचायत सभागार में महिला उत्पीड़न से संबंधित सुनीं शिकायतें,मा0 उपाध्यक्ष ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुचाने के लिए दिये निर्देश,महिला जनसुनवाई में प्राप्त हुई 09 शिकायते

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अपर्णा यादव ने जनपद भ्रमण के दौरान विकास खण्ड हरचंदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बालिकाओं के से वार्ता कर विद्यालय में मिल रही सुविधाओं/व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा बालिकाओं के साथ भोजन भी किया। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए बेहतर सुविधाएं और शिक्षा प्रदान की जाए।तत्पश्चात मा0 उपाध्यक्ष द्वारा विकास खण्ड हरचन्दपुर के प्यारेपुर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया जहां पर 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तथा आंगनबाड़ी केन्द्र पर मा0 उपाध्यक्ष द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की तथा बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया तथा केन्द्र पर उपस्थिति आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसके पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरचन्दपुर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया, कार्यक्रम में नवजात बच्चियों की दादी, नानी, बुआ, मौसी आदि के साथ केक काटकर व 25 महिलाओं को बेबी किट वितरित कर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को कन्या सुमंगला योजना के लाभ व महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5220 सहित अन्य योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इसके उपरान्त मा0 उपाध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत सभागार में महिला उत्पीड़न व उनकी समस्याओं से जुड़े मुद्दो के बारे में अधिकारियों से समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जन सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक समस्या, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा व रोजगार आदि संबंधी शिकायत सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसके पश्चात महिला आयोग मा0 उपाध्यक्ष ने बाल गृह (बालिका) चक धरौरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल गृह में रह रहे बच्चों की सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बाल गृह में रह रहे बच्चों से बातचीत की और उनसे बाल गृह में मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने बाल गृह के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। बच्चों को समय पर बेहतर भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी उन्होंने चर्चा की। महिला आयोग की मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के मनोरंजन और मानसिक सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित महिलाओ को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि महिलाओं के उत्पीड़न व महिला से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से किया जाये तथा महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत व ग्रामीण स्तर पर कराया जाये। जिन प्रकरणों में अभी कार्यवाही लंबित है उन्हें भी आयोग के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई की जाए। महिला जन सुनवाई के दौरान 09 शिकायत प्राप्त हुई जिन्हें शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। मा0 उपाध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं न्याय सुनिश्चित करना राज्य महिला आयोग की प्राथमिकता है और किसी भी पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसी दौरान मा0 उपाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि हॉस्पिटल में कन्या के जन्म होने पर महिलाओं को कन्या सुमंगला योजना की जानकारी प्रदान कराते हुए उनको उक्त योजना का लाभ दिलाया जाए, इसके लिए अस्पतालों में पोस्टर व पंपलेट डिस्प्ले कर महिलाओं को जागरूक किया जाए, जिससे शत प्रतिशत महिलाएं योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके, कोई भी लाभ से वंचित न रहें।

सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर पंपलेट चस्पा किए जाए, जिससे बच्चों को योजनाओं की जानकारी हो और वह घर जाकर अपने माता पिता को उन योजनाओं की जानकारी दे और वह उसका लाभ उठा सके। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी उबैर्दुरहमान, एसएचओ महिला थाना पुष्पा शर्मा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशी सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी वीरेन्द्र पाल, जिला मिशन कोऑर्डिनेटर शैफाली सिंह, जेण्डर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी, काउंसलर श्रद्धा सिंह, अर्चना सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत 48 लीटर अवैध कच्ची शराब व 320 किलो लहन बरामद, 04 अभियोग पंजीकृत

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 रोबिन आर्य एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 द्वारा मय हमराह विभिन्न स्थानों पर सघन दबिश की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान महराजगंज तहसील के थाना बछरावा अंतर्गत ग्राम पश्चिम गाँव, उफरापुर एवं नन्दाखेड़ा तथा थाना डीह क्षेत्र के ग्राम आटी एवं ठकुराइन का पुरवा स्थित अवैध कच्ची शराब निर्माण के अड्डों एवं संदिग्ध घरों पर छापेमारी की गई।छापेमारी के दौरान जनपद में कुल 48

लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 320 किलो लहन बरामद किया गया। बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कुल 4 अभियोग पंजीकृत किए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमलाः दिनेश यादव 'दादा'

शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग, कहा - छात्र शक्ति को कुचला नहीं जा सकता

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) वाराणसी/भदोही। सुरियावां क्षेत्र के ग्राम खरगपुर सनाथ पट्टी

निवासी युवा समाजसेवी एवं पूर्व छात्र नेता दिनेश कुमार यादव 'दादा' ने दिल्ली में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। 'दादा' ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर पर अपनी मांग रख रहे छात्र-छात्राओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया बर्बर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर सीधा हमला है। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर छात्र सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें और दोषियों को सजा मिले। लेकिन सरकार छात्रों की आवाज़ दबाने के लिए दमन का सहारा ले रही है। दिनेश यादव 'दादा' ने कहा कि आज पूरे देश के छात्र दिल्ली में आंदोलनरत हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री मौन हैं। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि तुरंत लाठीचार्ज की जांच हो, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो और छात्रों की मांगें मानी जाएं। अन्यथा युवा सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे।

रामगढ़ रोड़ रेलवे ओवरब्रिज के पास आवागमन की समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन की प्रभावी पहल

जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने किया संयुक्त निरीक्षण

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश के क्रम में रामगढ़ रोड़ स्थित निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के समीप आमजन एवं वाहनों के आवागमन में हो रही असुविधा के निस्तारण हेतु तहसीलदार सदर अमित सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए मौके पर ही निर्माण एजेंसी के साथ विस्तृत वार्ता की गई तथा आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। 100 मीटर लंबा एवं 5 मीटर चौड़ा लिंक मार्ग बनेगा, गुरुवार तक कार्य पूर्ण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य मार्ग से 100 मीटर लंबा एवं 5 मीटर चौड़ा वैकल्पिक लिंक मार्ग तत्काल तैयार कराया जाएगा। निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि गुरुवार तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी तय किया गया कि जब तक लिंक मार्ग तैयार नहीं हो जाता, तब तक रेलवे ओवरब्रिज के पूर्वी हिस्से में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। रोड़ पर केवल हल्के वाहन यानी दो पहियां व चार पहिया वाहन जाने की अनुति रहेगी। जिलाधिकारी ने समस्या के निराकरण हेतु कराई प्रभावी कार्रवाई-जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनसामान्य से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। लिंक मार्ग तैयार होने के बाद दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों का आवागमन और सुगमता से हो सकेगा तथा स्थानीय नागरिकों को आवागमन में हो रही असुविधा से राहत मिलेगी।

सेक्टर 61 में बाहुणा यात्रा महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

नोएडा। सेक्टर-61 स्थित रॉयल गार्डन इस्टेट परिसर में स्थित श्री स्वर्ण क्षेत्र में भव्य समारोह के रूप में बाहुड़ा यात्रा उत्सव मनाया गया। इस पवित्र पर्व के अवसर पर सुबह से ही कम्युनिटी सेंटर स्थित मंडप में चारो ठाकुरों की स्थापना कर परंपरागत हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार अलग-अलग पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई। सुबह 8 बजे ठाकुरों के घोड़े/रथ पर प्रतिष्ठा कर विजय यात्रा आरंभ हुई। पहली बार यहाँ आयोजित इस बाहुड़ा यात्रा में सेक्टर-61, 52, 53 व 33 में रहने वाले ओड़िया व गैर-ओड़िया लगभग 2000 भक्तों की उपस्थिति देखी गई। हिन्दू सम्मिलनी समिति, रॉयल गार्डन इस्टेट मंदिर समिति और सामुदायिक विकास समिति की संयुक्त पहल से आयोजित इस आयोजन में श्रद्धालुओं व आयोजकों में उल्लास और उत्साह देखा गया। 16 जुलाई से 23 जुलाई तक 8 दिनों तक भगवद कथा एवं जगन्नाथ कथा शरणपुर के आचार्य अजय किरण द्वारा संचालित की गई। नॉएडा महानगर के कई गणमान्य व्यक्ति भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में विशेष अतिथि एवं सहभागी के रूप में महेश चौहान (अध्यक्ष, नोएडा महानगर बीजेपी), उपाध्यक्ष प्रमोद भल्ला (नाम का उच्चारण मूल पाठ के अनुसार), ओमबीर आना/आवाना, मंडल अध्यक्ष

रामकिशन यादव, पंकज झा, श्रीमती विमला बाथम (नोएडा की पूर्व विधायक), गुरुजी गौतम ऋषि, योगेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष FONERV एन.पी. सिंह, अध्यक्ष DDRWA विकास अग्रवाल, अध्यक्ष भारत विकास परिषद डॉ. राजेश सहाय, तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। आयोजक तथा मुख्य संयोजक समाजसेवी व प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट डॉ. मनोरंजन महान्ति (अध्यक्ष) तथा सुश्री नीरू शर्मा (सचिव) के सक्रिय तत्त्वावधान में लगभग 200 स्वयंसेवकों द्वारा सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराए गए। गुरुजी डॉ. गौतम ऋषि, जो एक सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य हैं, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और परम्परागत विधि-अनुसार छेड़ा-पहँराव व अन्य अनुष्ठानों का समुचित रूप से संचालन किया। इसके बाद सुबह 9 बजे रथटाना का कार्य प्रारम्भ हुआ। चारों ठाकुरों से सुसज्जित सुंदर रथों को सेक्टर-61 के कम्युनिटी सेंटर से श्री स्वर्ण क्षेत्र, रॉयल गार्डन इस्टेट तक लाया गया। मार्ग के दोनों ओर कतारों में खड़े भक्तों ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किए और जगत नाथ जगन्नाथ के दर्शन पाकर कृतज्ञता व्यक्त की – इस दृश्य ने उपस्थितों के हृदय को छू लिया।

चतुर्धा मूर्ति – श्री जगन्नाथ, श्री बालभद्र, माता सुवेधा (सुभद्र) तथा श्री सुन्दर्शन – बाहुड़ा यात्रा कर दोपहर 11 बजे के आसपास पुनः श्री स्वर्ण क्षेत्र मंदिर में लौट आईं।

यह धार्मिक व सांस्कृतिक महोत्सव 'आरंभ टीवी' के माध्यम से भी सीधा प्रसारित किया गया।

क्षय रोगियों को वितरित की गई पोषण पोटली, टीबी मुक्त भारत अभियान को मिला नया बल

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) रायबरेली। कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका

द्वारा क्षय रोगियों के लिए पोषण सहायता अभियान का शुभारंभ किया गया था। उसी क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 नवीन चंद्रा के दिशा-निर्देशन में बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट रायबरेली के सहयोग एवं विश्वास संस्थान, रायबरेली द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईसीडीपी) के अंतर्गत गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमावा में 101 चिन्हित क्षय रोगियों में से प्रथम चरण में 65 क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित की गई। शेष 36 रोगियों को दूसरे चरण में पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम से पूर्व बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं विश्वास संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता से शिष्टाचार भेंट कर अभियान की रूपरेखा से अवगत कराया था। मुख्य विकास अधिकारी ने इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की थीं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने कहा, 'टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में शासन, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक संस्थाओं एवं कॉर्पोरेट संस्थानों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं विश्वास संस्थान द्वारा किया जा रहा यह कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है तथा इससे क्षय रोगियों को उपचार के साथ आवश्यक पोषण भी उपलब्ध हो रहा है।'कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनुपम सिंह ने पोषण पोटली वितरित करते हुए कहा, 'टीबी पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी है। यदि मरीज नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करें तथा पौष्टिक आहार लें तो वे पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। सभी मरीज उपचार बीच में न छोड़ें और अपने आसपास के लोगों को भी टीबी के लक्षणों के प्रति जागरूक करें।'सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमावा के अधीक्षक डॉ. रोहित कटियार ने कहा, 'सरकारी विभाग, सामाजिक संस्थाएं एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की साझेदारी से जनस्वास्थ्य से जुड़े अभियान और अधिक प्रभावी बनते हैं।' बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट रायबरेली के प्रतिनिधि शिव गोविंद सिंह ने कहा, 'कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत हमारी संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। क्षय रोगियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।'विश्वास संस्थान के परियोजना अधिकारी प्रशांत शुक्ला ने कहा, 'हमारा प्रयास है कि प्रत्येक चिन्हित क्षय रोगी तक पोषण सहायता पहुँचे और उनके उपचार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।'उत्तर प्रदेश क्षय रोग वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष करुणा शंकर मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। बिरला कॉरपोरेशन एवं विश्वास संस्थान का सहयोग निश्चित रूप से इस अभियान को नई मजबूती प्रदान करेगा। प्रथम चरण के बाद शेष चिन्हित रोगियों को भी दूसरे चरण में पोषण पोटली उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर डॉ. अभिजीत सिंह ने जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अनुपम सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में अपूर्व मिश्रा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, विश्वास संस्थान के परियोजना अधिकारी प्रशांत शुक्ला, सहायक अनिल प्रजापति, अजय कुमार, कप्तान सिंह, बीसीपीएम चंद्र किशोर यादव, दिव्यांशु वर्मा, मनोज सिंह, प्रमिला वर्मा, उत्तम, खुर्शीद आलम, वैभव, रामबली, 65 क्षय रोगी तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एआईएमसीईए की जनपद बिलासपुर - छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी का हुआ गठन

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) छत्तीसगढ़/बिलासपुर। ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी

एजुकेटेड एसोसिएशन (एआईएमसीईए) छत्तीसगढ़, जनपद बिलासपुर की एक आवश्यक बैठक का आयोजन प्रीत होटल, बिलासपुर में मणि शंकर श्रीवास की अध्यक्षता में संपन्न हुई । इस बैठक में प्रयागराज से पधारे ऑल इंडिया एम सी ई ए के संगठन सचिव आदित्य नारायण सेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । मुख्य अतिथि का स्वागत बुके तथा अंगवस्त्र देकर किया गया। बैठक का संचालन राष्ट्रीय कार्यकारणी के उपाध्यक्ष अमित श्रीवास ने किया । बैठक प्रारंभ करने से पहले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के चित्र पर मुख्य अतिथि तथा अन्य लोगों द्वारा माल्यार्पण पुष्पार्पण किया गया। सभा को संबोधित करते हुए आदित्य नारायण सेन राष्ट्रीय संगठन सचिव ने ऑल इण्डिया एम सी ई ए के गठन, परिचय तथा उद्देश्य पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला तथा उपस्थित लोगों से इस गौरवशाली संगठन से जुड़ने का आह्वान किया । उन्होंने सम्राट महापद्मनंद का विस्तृत इतिहास लोगों को बताया तथा इस गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने की अपील किया । बैठक को अमित श्रीवास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने संबोधित करते हुए सभी लोगों से इस गौरवशाली संस्था से जुड़ने के लिए आग्रह किया तथा पे बैक टु सोसायटी की भावना से सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया ।

इस सभा में अंकित श्रीवास, रमेश ठाकुर ,नरेंद्र श्रीवास ,मणि शंकर श्रीवास, गणेश श्रीवास, रमेश श्रीवास , वीरेंद्र श्रीवास, आनन्द श्रीवास,गोपाल जी श्रीवास ,सुरेंद्र कुमार सेन, रवीन्द्र सिंह सेन आदि ने भी बैठक को संबोधित किया । बैठक में सर्वसम्मति से जनपद बिलासपुर कार्यकारिणी का विधिवत मनोनयन किया गया । जिसमें अध्यक्ष अंकित श्रीवास अध्यक्ष ,रमेश ठाकुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नरेंद्र श्रीवास उपाध्यक्ष, मणि शंकर श्रीवास सचिव ,गणेश श्रीवास उप सचिव ,संगठन सचिव रमेश श्रीवास, संगठन सचिव वीरेंद्र सेन, कोषाध्यक्ष आनंद श्रीवास, मीडिया प्रभारी गोपाल श्रीवास तथा सुरेंद्र कुमार सेन सदस्य कार्यकारिणी मनोनीत किए गए । मनोनीत सभी पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि आदित्य नारायण सेन ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई । सभा को मणिशंकर श्रीवास ने संबोधित करते हुए सभा के समाप्ति की घोषणा किया । यह जानकारी एआईएमसीईए के मीडिया प्रभारी गोपाल श्रीवास ने एक विज्ञप्ति में दी है ।

आईएमएस नोएडा में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन, धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध के प्रति जागरूकता अभियान होगा संचालित

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) नोएडा। सेक्टर-62 स्थित

आईएमएस नोएडा में छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों के बीच तंबाकू एवं धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा संस्थान परिसर को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया। यह समिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से गठित की गई। समिति का मुख्य उद्देश्य संस्थान में तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध संबंधी नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, छात्रों एवं कर्मचारियों को तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ एवं स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देना है। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की संयोजक बर्षा छबारिया ने बताया कि संस्थान की ओर से प्रोफेसर डॉ. वर्तिका चतुर्वेदी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताएं, विशेषज्ञ व्याख्यान, परामर्श सत्र तथा तंबाकू निषेध संबंधी जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही संस्थान परिसर में धूम्रपान

एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रकोष्ठ की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉ. वर्तिका चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवनशैली, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सकारात्मक आदतों का विकास करना भी है। तंबाकू नियंत्रण समिति के माध्यम से संस्थान विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को नशामुक्त एवं स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि आईएमएस नोएडा सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों से अपील करता है कि वे तंबाकू मुक्त परिसर बनाए रखने में सक्रिय सहयोग दें तथा स्वयं भी तंबाकू एवं धूम्रपान से दूर रहकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। संस्थान परिसर में आज आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सफाईकर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को तंबाकू एवं धूम्रपान के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर उन्हें तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, कैंसर एवं अन्य घातक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई तथा तंबाकू मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को तंबाकू एवं धूम्रपान का सेवन न करने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही संस्थान परिसर को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया।

'कंपनी के करिंदा के रुप में सोनभद्र प्रशासन कर रहा काम- संदीप मिश्रा

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। ससनई के ग्रामीण

पहुंचे जिला अधिकारीकार्यालय मामले का गंभीरता नहीं लिए जिलाधिकारी वहीं किसान नौजवान' संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने जिलाधिकारी चर्चित सिंह गौड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन वनाधिकार पट्टाधारकों को पूर्व में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि का अधिकार दिया गया था, उन्हें अब कंपनी स्थापित कराने के उद्देश्य से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन कंपनी के हित में कार्य कर रहा है और वनवासियों एवं आदिवासी परिवारों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत दिए गए पट्टों को निरस्त करने या लोगों को उनकी भूमि से बेदखल करने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण कन्हैयालाल चेरो ने कहा कि 'हम अपनी पट्टे की जमीन किसी भी कीमत पर कंपनी को नहीं देंगे। चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे।' वहीं ज्ञानमती देवी ने भी कहा कि 'हम लोग किसी भी हाल में अपनी जमीन कंपनी को नहीं देंगे। भले ही जिलाधिकारी नोटिस जारी करते रहें, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' संदीप मिश्रा ने कहा कि संघर्ष मोर्चा लंबे समय से 'पेड़ है तो प्राण है' अभियान के माध्यम से जंगल, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चला रहा है।यदि कंपनी लगाने के नाम पर वनाधिकार पट्टाधारकों और ग्रामीणों के अधिकारों का हनन किया गया तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज के कार्यक्रम में कन्हैया चेरो विजय चेरो ज्ञानमति राजेश चेरो दिनेश चेरो विन्दू खरवार मुखलाल चेरो व उमाशंकर यादव राजू पासवान सैकड़ों आदिवासी परिवारि जन उपस्थित रहे।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सोनभद्र द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को 15 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र श्री ओमकार शुक्ला ने सत्र परीक्षण संख्या 279/2025, राज्य बनाम रमाशंकर में अभियुक्त रमाशंकर पुत्र स्व. शिवभजन, निवासी ग्राम बेलहत्थी टोला पिरहवा, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र को दोषसिद्ध ठहराते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार, दिनांक 26 जनवरी 2025 को अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ अश्लील हरकत एवं बलात्कार की घटना कारित की। पीड़िता की छोटी बहन के विरोध करने पर उसको रेलवे ट्रैक पर जान मारने की धमकी देते हुए धक्का दे दिया जिससे उसका दाहिना पैर पंजे के ऊपर से कटकर अलग हो गया और उसे गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में थाना हाथीनाला पर मुकदमा अपराध संख्या 3/2025 पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान पीड़ितागण का चिकित्सीय परीक्षण, आयु संबंधी अभिलेख, एफएसएल रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 12 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा आवश्यक दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त को धारा 64(1), 74, 117(3), 351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं रु20,000 अर्थदण्ड, धारा 117(3) बीएनएस में 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं रु20,000 अर्थदण्ड, धारा 74 बीएनएस में 2 वर्ष का कारावास एवं रु5,000 अर्थदण्ड तथा धारा 351(2) बीएनएस में 1 वर्ष का कारावास एवं रु1,000 अर्थदण्ड से दंडित किया। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। अर्थदण्ड की आधी राशि पीड़िता तथा आधी राशि घायल बालिका के पुनर्वास हेतु दिए जाने का आदेश भी पारित किया गया। राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा प्रभावी रूप से किया गया।

जनपद में सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक, प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़

एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अल्ट्राटेक के सीएसआर फंड के माध्यम से आधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराए जाएंगे। इन कैमरों को जनपद के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, दुर्घटना बहुल क्षेत्रों, बाजारों, संवेदनशील स्थानों, चोरी एवं आपराधिक घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर लगाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना तथा नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। वर्षभर होगी सतत निगरानी, कानून-व्यवस्था होगी और मजबूतः-यह सीसीटीवी व्यवस्था किसी विशेष आयोजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वर्षभर निरंतर संचालित रहेगी। कैमरों के माध्यम से जनपद की कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की गतिविधियों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जाएगी। इससे अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित नजर, यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने तथा किसी भी आपात स्थिति में शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन एवं पुलिस को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। यह आधुनिक निगरानी प्रणाली सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। अपराध नियंत्रण एवं त्वरित कार्रवाई में मिलेगी सहायताः- सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चोरी, लूट, तोड़फोड़ एवं अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के साथ-साथ अपराधियों की शीघ्र पहचान एवं गिरफ्तारी में भी सहायता मिलेगी। साथ ही यातायात संचालन, सार्वजनिक गतिविधियों की निगरानी तथा विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन में भी यह प्रणाली उपयोगी सिद्ध होगी। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से की सहयोग की अपीलः- जिलाधिकारी ने जनपदवासियों, व्यापारियों, प्रतिष्ठान संचालकों एवं संस्थानों से अपील की है कि वे भी अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों, आवासों, कार्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण परिसरों में स्वेच्छा से सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं। नागरिकों की सहभागिता से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी तथा चोरी, लूट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के साथ-साथ अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अपराधमुक्त जनपद के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अल्ट्राटेक के सीएसआर फंड से स्थापित होगी आधुनिक निगरानी प्रणाली

मुख्यमंत्री गो-संवर्धन योजना के तहत ई-लॉटरी से 28 लाभार्थियों का हुआ चयन,506 आवेदनों में से पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया चयन

योजना से पशुपालकों की आय बढ़ाने एवं जीवन स्तर सुधारने का मिलेगा अवसर

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की

अध्यक्षता में मुख्यमंत्री गो-संवर्धन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु ई-लॉटरी का आयोजन किया गया। योजना के लिए प्राप्त 506 आवेदनों में से ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 28 लाभार्थियों का चयन किया गया। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री गो-संवर्धन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए उनकी आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि ई-लॉटरी के माध्यम से चयनित लाभार्थियों के अभिलेखों का परीक्षण पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में भविष्य में प्राप्त आवेदनों के आधार पर पुनः ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया भी संचालित की जाएगी।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कला, मेहंदी प्रतियोगिता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन,एक वृक्ष मां के नाम अभियान के अंतर्गत हुआ पौधरोपण, छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। जिलाधिकारी के निर्देशन, मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन तथा

जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पुनीत टंडन के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग, सोनभद्र द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत द आर्यन एकेडमी, संत नगर, रॉबर्ट्सगंज में कला एवं मेहंदी प्रतियोगिता, पौधरोपण तथा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कला प्रतियोगिता में कक्षा 5 की माही ने प्रथम, कक्षा 7 की परी मिश्रा ने द्वितीय तथा कक्षा 7 की अनिका त्रिपाठी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में कक्षा 9 की मानवी मौर्या प्रथम, कक्षा 9 की शुभांगी मौर्या द्वितीय एवं कक्षा 6 की अनुराधा राजवंशी तृतीय स्थान पर रहीं। विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के महत्व के साथ महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जेंडर स्पेशलिस्ट साधना मिश्रा ने महिला हेल्पलाइन-181, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, आपातकालीन सेवा-112 एवं साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 के संबंध में जागरूक करते हुए बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण पर विस्तार से जानकारी दी। दीपिका सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती चित्रा जालान ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण करते हुए ष्बेटियां बचेंगी तभी पढ़ेंगी, बेटी है तो कल है तथा पौधा है तो जीवन हैष् का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्या श्रीमती चित्रा जालान, दीपिका सिंह, साधना मिश्रा, शिक्षक-शिक्षिकाएँ उमाकांत दुबे, महेश त्रिपाठी, निशा चौबे, यासमीन, सुषमा पांडे, प्रिया, सुमन, अर्पणा सहित 127 छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE
(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)
सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एण्ड इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी
फायर सेफ्टी पर जिसकी कमाण्ड, उसकी ही है ग्लोबल डिमाण्ड
कोर्स के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल जाती है। रिलीफ एजेन्सी N.G.O., डिफेन्स सर्विसेज फायर सर्विस आर्डिनेन्स फैक्ट्री, महानगर पालिका, नगर निगम, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, स्टील प्लान्ट, माइनिंग इन्डस्ट्रीज, पेट्रोलियम कम्पनी, फूड इण्डस्ट्रीज, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल मिल, टावर कम्पनी, इलेक्ट्रानिक कम्पनी, कोयले की खदानों एवं जहाजों आदि क्षेत्रों में फायर सेफ्टी के जानकारों को बहुत अधिक मौका मिलता है

नोटः फायर सेफ्टी कोर्स करें और देश -विदेश, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पायें।
Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480

कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर भारतीय दल की अगुआई की, किंग चार्ल्स ने किया उद्घाटन

ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई। ओवो हाइड्रो एरिना में दो बार की ओलिंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और टोक्यो ओलिंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर 125 सदस्यीय भारतीय दल की अगुआई की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने खेलों का उद्घाटन किया। इसके बाद भारत समेत 74 देशों के खिलाड़ियों ने मार्च-पास्ट में हिस्सा लिया। भारत के लिए खेलों की शुरुआत भी शानदार रही। उद्घाटन समारोह से पहले ही भारतीय खिलाड़ियों ने लॉन बॉल्स में दो जीत दर्ज कर विजयी आगाज किया। पुतुल सोनोवाल ने वर्ल्ड चैम्पियन कनाडा के रेयान बेस्टर को मात दे दी। महिला डबल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी ने भी अपना पहला मैच जीता। भारतीय जोड़ी ने 'ग्रुप बी' के मैच में माल्टा की रिक्कसन बहनों (रेबेका लुईस और कोनी-लेघ) को टाईब्रेकर में हराया। वहीं भारतीय ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहेन महिला 75 किलोग्राम वर्ग में सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण बिना मुकाबला खेले ही कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर चुकी हैं। स्कॉटलैंड की संस्कृति से हुई शुरुआत, किंग चार्ल्स ने किया उद्घाटन- ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत स्कॉटलैंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत के विशेष वीडियो से हुई। इसके बाद किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला एरिना पहुंचे। उनके साथ प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम भी मौजूद रहे। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रगान 'गॉड सेव अवर किंग' प्रस्तुत किया गया और फिर एक-एक कर सभी 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने मार्च-पास्ट किया। भारत 125 खिलाड़ियों के साथ उतरा-23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इन खेलों में भारत 125 खिलाड़ियों का दल भेजा है। ओपनिंग सेरेमनी ग्लासगो के ओवो हाइड्रो एरिना में हुई, जहां करीब 13 हजार दर्शक मौजूद रहे। भारतीय दल इस बार एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, लॉन बॉल्स समेत 10 खेलों में चुनौती पेश करेगा। बैगपाइप की धुन पर झूमे दर्शक- मार्च-पास्ट खत्म होने के बाद स्कॉटलैंड की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाला कार्यक्रम हुआ। पारंपरिक बैगपाइप की धुन, स्थानीय कलाकारों के संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उद्घाटन समारोह को यादगार बना दिया।

वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, फिफ्टी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने, अर्धशतक मां को समर्पित किया

हरारे। भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे के हरारे ग्राउंड में खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी

इंटरनेशनल में फिफ्टी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। मुकाबले में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी आए। सूर्यवंशी ने फिफ्टी लगाने के बाद अपनी मां के नाम का पहला लेटर ए का साइन बनाया। उनकी मां का नाम आरती सूर्यवंशी है। भारत बनाम ज़िम्बॉम्बे मैच के टॉप रिकॉर्ड्स मोमेंट्स- 1. सूर्यवंशी ने सचिन के यंगेस्ट फिफ्टी का रिकॉर्ड तोड़ा-सूर्यवंशी इंटरनेशनल में फिफ्टी लगाने वाले दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने 15 साल 118 दिन की उम्र में फिफ्टी लगाई। वे फुल मेंबर देशों में ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 213 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था। सूर्यवंशी ने ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल के कुशल मल्ला का रिकॉर्ड तोड़ा। मल्ला ने 2020 में अमेरिका के खिलाफ वनडे में 15 साल 340 दिन की उम्र में फिफ्टी लगाई थी। 2. सूर्यवंशी टी-20 में फिफ्टी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर- सूर्यवंशी 15 साल 118 दिन की उम्र में टी-20 में फिफ्टी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने जिब्राल्टर के लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा। लुई ने माल्टा के खिलाफ 16 साल 56 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था। 3. जिम्बाब्वे में 23 भारतीयों ने टी-20 डेब्यू किया-विदेश में सबसे ज्यादा भारतीयों ने टी-20 डेब्यू जिम्बाब्वे में किया है। अशोक शर्मा जिम्बाब्वे में टी-20 डेब्यू करने वाले 23वें भारतीय बने। ओवरऑल भारत में ही सबसे ज्यादा इंडियंस ने टी-20 डेब्यू किया है। देश में 31 भारतीय टी-20 डेब्यू कर चुके हैं। 4. मयंक यादव ने दूसरी बार टी-20 की पहली गेंद पर विकेट लिया-मयंक यादव ने पारी की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को कैच आउट कराया। उन्होंने करियर में दूसरी बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लिया। उनसे पहले हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह भी 2-2 बार यह कारनामा कर चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार 3 बार के साथ लिस्ट में

पहले स्थान पर हैं। 5. भारत ने 40 गेंद रहते टारगेट हासिल किया- भारत ने 40 गेंद रहते 126 रन का टारगेट हासिल कर लिया। 120 से ज्यादा के टारगेट में भारत का यह चौथा सबसे तेज रनचेज है। टीम ने इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज रनचेज किया था। तब भारत ने 154 रन का टारगेट 60 गेंद बाकी रहते हासिल किया था। यहां से टॉप-3 मोमेंट्सः-1. अशोक शर्मा ने टी-20 डेब्यू किया-राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने टी-20 डेब्यू किया। अशोक आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की ओर से खेले थे। उन्होंने इस सीजन 6 मैचों में 6 विकेट लिए थे। 2. प्रिंस यादव की लगातार 2 गेंद पर विकेट गिरा-20वें ओवर में जिम्बाब्वे ने लगातार 2 गेंद पर विकेट गंवाए। प्रिंस यादव के ओवर की दूसरी गेंद पर मधेवेरे दूसरा रन लेने की कोशिश में रनआउट हुए। इसकी अगली ही गेंद पर ब्रैड इवांस बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मिड-ऑफ पर श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे। इवांस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। 3. सूर्यवंशी ने फिफ्टी के बाद ए का साइन बनाया-सूर्यवंशी ने अपनी फिफ्टी मां को डेडिकेट की। उन्होंने फिफ्टी पूरा करने के बाद दोनों हाथों से ए का साइन बनाया। सूर्यवंशी ने बताया था कि वे इस साइन के जरिए अपनी मां को ट्रिब्यूट देते हैं। उनकी मां का नाम आरती है। उन्होंने 50 रन की पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए।

बारिश के मच्छर फैलाते डेंगू-मलेरिया,10 लक्षणों को इग्नोर न करें, डॉक्टर से जानें बचाव के लिए 8 सावधानियां

जयपुर। बारिश के मौसम में जगह-जगह जमा पानी और नमी के कारण मच्छर तेजी से पनपते हैं। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी कई बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। दूषित पानी और भोजन के कारण टाइफॉइड, हैजा और फूड पॉइजनिंग का जोखिम भी बढ़ता है। अक्सर लोग इन बीमारियों के लक्षणों को सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि कुछ बुनियादी सावधानियां बरतकर इनके रिस्क को कम किया जा सकता है। इसलिए आज 'फिजिकल हेल्थ' में बारिश में होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि- किन लोगों को इन बीमारियों का रिस्क ज्यादा होता है? बारिश में बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? विषय को समझेंगे एक्सपर्टः डॉ. रोहित शर्मा, कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर जी के साथ सवाल जवाब के माध्यम से। सवाल- बारिश में कौन-सी बीमारियां फैलती हैं? जवाब- बारिश के मौसम में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। साथ ही जगह-जगह पानी रुकने से मच्छर पनपते हैं। इससे इन बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है- मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग, हैजा, वायरल फीवर। सवाल- बारिश में अधिकांश बीमारियां मच्छरों के कारण क्यों फैलती हैं? जवाब- बारिश में अधिकांश बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं क्योंकि- बारिश में जगह-जगह पानी जमा हो जाता है। यह मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण है। इस मौसम में नमी ज्यादा होती है। इससे मच्छर तेजी से पनपते हैं और उनकी संख्या बढ़ जाती है। बारिश के बाद घरों के आसपास रखे गमले, कूलर, टायर, बाल्टी और छतों पर जमा पानी मच्छरों का ठिकाना बनते हैं। ये मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। सवाल- किन लोगों को इन बीमारियों का रिस्क ज्यादा होता है? जवाब- बारिश में फैलने वाली बीमारियों का रिस्क इन लोगों को ज्यादा होता है- जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जिन्हें अस्थमा है। जिन्हें डायबिटीज है। सवाल- डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल फीवर में फर्क कैसे पहचानें? जवाब- लक्षणों के आधार पर इन तीनों के बीच के फर्क को समझा जा सकता हैः- डेंगू-तेज बुखार (104ष्टइ तक), आंखों और मसल्स में दर्द, लाल चकत्ते, बहुत कमजोरी। मलेरियाः-कंपकंपी के साथ बुखार, बुखार के बाद पसीना, हर 1-2 दिन में बुखार, कमजोरी, उल्टियां। चिकनगुनियाः-तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन, बहुत थकान। वायरल फीवरः- हल्का से मध्यम बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द। मसल्स में दर्द। बुखार के ये लक्षण इग्नोर न करें-बार-बार उल्टी या पेट दर्द हो। 3 दिन से ज्यादा बुखार हो। दवा लेने पर आराम न हो। चक्कर आए या बेहोशी हो। सांस लेने में दिक्कत हो। सिर, आंखों में सीने में तेज दर्द हो। दर्द हो। पेशाब या उल्टी में खून आए। जोड़ों में असहनीय दर्द, सूजन हो। सवाल- घर के आसपास किन जगहों पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं? जवाब- कुछ जगहों पर मच्छर पनपने का रिस्क ज्यादा होता है, जैसेकि- कूलर, पानी की टंकी- कई दिनों तक पानी जमा रहने से इनमें मच्छर तेजी से पनपते हैं। बाल्टी, ड्रम, खुले बर्तन- बिना ढके रखने पर इनमें पानी रुक जाता है। गमले, पौधों की ट्रे- नीचे जमा पानी मच्छरों के लिए अनुकूल जगह है। पुराने टायर, बोतलें, डिब्बे- इनमें बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रहता है। घर के आसपास गड्ढे- निकासी न होने पर पानी लंबे समय तक जमा रहता है। नालियां, ड्रेनेज सिस्टम- गंदा और रुका पानी मच्छरों को आकर्षित करता है। फ्रिज, एसी की वाटर ट्रे- ये जगहें अक्सर नजरअंदाज होती हैं, लेकिन मच्छर यहां भी पनपते हैं।कचरे के डिब्बे, खुले कंटेनर- ढक्कन न होने पर पानी जमा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स- यहां गड्ढों में पानी भर जाता है। सवाल- घर के अंदर मच्छरों को पनपने से कैसे रोकें? जवाब- इसके लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं- घर में कहीं पर भी पानी जमा न होने दें। कूलर, बाल्टी, फूलदान और ट्रे का पानी हर 2-3 दिन में बदलें। हफ्ते में कम-से-कम एक बार कूलर की सफाई करें। पानी के बर्तन, टंकी, ड्रम और बोतल हमेशा बंद रखें। फ्रिज/एसी की ट्रे रेगुलर साफ करें। खिड़की-दरवाजों पर जाली लगाएं। मच्छरदानी या रेपलेंट का इस्तेमाल करें। कचरा जमा न होने दें। रेगुलर सफाई करें। सवाल- बारिश में बीमारियों से बचने के लिए घर में कौन-सी सावधानियां जरूरी हैं? जवाब- इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखें- साफ और ढका हुआ पानी इस्तेमाल करें। पीने का पानी उबालकर या फिल्टर करके यूज करें। सोते समय मच्छरदानी/रेपलेंट का उपयोग करें। घर की नियमित सफाई रखें, नालियां साफ रखें। ताजा खाना खाएं और उसे हमेशा ढककर रखें। बाहर का कच्चा या बासी खाना न खाएं। गीले कपड़े न पहनें। खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथ जरूर धोएं। सवाल- बीमारियों से बचाव में इम्यूनिटी का क्या रोल है? जवाब- बारिश में फैलने वाली बीमारियों, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल फीवर से बचाव में इम्यूनिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इम्यूनिटी हमारे लिए ये जरूरी काम करती है- 1. संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है-मजबूत इम्यूनिटी शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। इससे बीमारी का रिस्क कम हो जाता है। 2. बीमारी का असर कम करती है- अगर संक्रमण हो भी जाए, तो अच्छी इम्यूनिटी के कारण लक्षण हल्के रहते हैं और रिकवरी जल्दी होती है। 3. बार-बार बीमारी नहीं होती है-कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं, जबकि मजबूत इम्यून सिस्टम शरीर को संक्रमण से बचाता है। 4. कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम करती है-मजबूत इम्यून सिस्टम ज्यादा कमजोरी होने और प्लेटलेट्स गिरने जैसी गंभीर स्थिति बनने से रोकता है। अच्छी इम्यूनिटी होने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब है कि संक्रमण होने पर शरीर उससे बेहतर तरीके से लड़ पाएगा और रिकवरी भी जल्दी होगी। इसलिए मच्छरों से बचने के साथ-साथ इम्यूनिटी भी मजबूत करें। सवाल- इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? जवाब- बारिश के मौसम में इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए ऐसा खाना खाएं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत दे और पाचन में भी हल्का होः-विटामिन सी- संतरा, नींबू, आंवला-इम्यूनिटी मजबूत होती है। हरी सब्जियां- पालक, मेथी, लौकी, तोरई- जरूरी विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। हर्ब्स-अदरक, लहसुन, हल्दी-ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं। प्रोटीन-दालें, पनीर, अंडा- शरीर के लिए अनिवार्य हैं। प्रोबायोटिक्स-दही और छाछ-गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। ड्राई फ्रूट्स- बादाम, अखरोट, पिस्ता-जरूरी पोषण मिलता है। हर्बल ड्रिंक्स- काढ़ा, ग्रीन टी, अदरक चाय- इम्यूनिटी मजबूत होती है। सवाल- बारिश के मौसम में क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? जवाब- बारिश के मौसम में ये चीजें बिलकुल न खाएं, जैसेकि- 1. खुले में रखे कटे फल, खुले में रखा होने से इन पर धूल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। 2. स्ट्रीट फूड (चाट, गोलगप्पे) गंदे पानी और अनहाइजीनिक तरीके से बने होने से फूड पॉइजनिंग और हैजा जैसी बीमारियों का रिस्क होता है। 3. बासी खाना-जल्दी खराब होता है और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। 4. कच्ची या अधपकी सब्जियां इनमें बैक्टीरिया और कीड़े हो सकते हैं। 5. पत्तेदार सब्जियां- इनमें मिट्टी और कीटाणु चिपके हो सकते हैं। 6. बिना उबला या अनफिल्टर्ड पानी-दूषित पानी पीने से बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। 7. ज्यादा तला-भुना और जंक फूड-पाचन खराब करता है और इम्यूनिटी कमजोर करता है।

क्या कुछ करियर में 'डीजे' अकेलापन दूर करने का तरीका है?

हमारी कुक कमला शाहू महीने में कम-से-कम दस बार हमसे शिकायत करती हैं कि वे कभी भी रात 2 बजे से पहले नहीं सो पातीं। ऐसा तब है, जब वे रोज रात 8 बजे हमारे घर से चली जाती हैं और पांच मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहती हैं। इसकी वजह उनका तीसरा अविवाहित बेटा सतीश है, जो नौकरी के बाद डिस्क जॉकी (डीजे) का काम भी करता है और होटल से रात 1.30 बजे लौटता है। कमला उसे खाना परोसने के बाद ही सो पाती हैं। पिछले महीने जब सतीश की शादी हुई, तो मैंने यूं ही उससे कहा कि चूंकि तुम्हारी शादी हो गई है तो अब डीजे का काम छोड़ सकते हो। लेकिन सतीश ने मुझे अलग नजरिया दिया। उसने बताया कि वह एक बड़ी फर्म के बैकएंड में काम करता है, जहां अकेलापन बहुत परेशान करता है। इसलिए डीजे पूरे दिन क्रिएटिव बने रहने में उसकी मदद करता है। उसने कहा कि 'डीजे म्यूजिक पूरी तरह जाने-पहचाने साउंड्स को नए संदर्भ में पेश करने पर आधारित होता है। कोई अनपेक्षित मैश-अप या चतुराई भरे ट्रांजिशन को सुनना आपके दिमाग को डीजे का काम करते हैं, क्योंकि यह कई अहम तरीकों से आपकी कल्पनाशक्ति बढ़ाने के लिए ताकतवर उत्प्रेरक का कार्य करता है। घर लौटकर मैंने उन प्रमुख आंत्रप्रेन्योर्स की सर्च की, जो कॉग्निटिव क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए डीजे म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं। जाहिर तौर पर डीजे सेट्स के साथ जुड़ने से उन खास न्यूरल पाथ-वे की एक्सरसाइज होती है, जो इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल एक्सप्रेशन से संबंधित होते हैं। ऑनलाइन जिस पहले व्यक्ति का नाम मुझे दिलचस्प लगा, वह लंदन की फैमिली लॉ फर्म 'साउथगेट सॉलिसिटर्स' के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हसन हादी थे। उन्होंने पिछले साल डीजेइंग शुरू की और पाया कि इससे न सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी में फायदा हुआ, बल्कि वे काम पर फोकस भी कर पाते हैं। सतीश का भी यही दावा है। शौकिया डीजेइंग करने वाले फाउंडर्स में गोल्डमैन सैक सिखाता है कि रोजमर्रा के काम में भी दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट को कैसे जोड़ा जाए।' उसने कहा कि दुनिया के कई बेहद अमीर आंत्रप्रेन्योर्स कुछ घंटों के लिए सिंथेसिस के को-फाउंडर और चीफ एक्जीक्यूटिव विक्टर रिपरबेली शामिल हैं। शॉपिफाई के प्रेसिडेंट हार्ले फिंकेलस्टीन ने किशोरावस्था में डीजे कंपनी शुरू की थी और आज भी अकसर अपनी कंपनी के कॉरपोरेट इवेंट्स में डीजेइंग करते हैं। रोजमर्रा में हादी अपनी लॉ फर्म का मैनेजमेंट, नेतृत्व और सुपरविजन संभालते हैं। हालांकि अब वे केसवर्क नहीं देखते, लेकिन युवा कानूनी पेशेवरों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करते हैं। वे कहते हैं, 'दिन में लॉ फर्म मैनेज करना और फिर डीजेइंग करना, दोनों के लिए समान स्किल चाहिए।' वे सही भी हैं।

वकीलों और डीजे, दोनों को माहौल समझना पड़ता है, उसी स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तात्कालिक परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। चाहे अदालत में सुनवाई हो या क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग, दोनों में ही मौके के अनुसार ही खुद को ढालना पड़ता है। दिलचस्प यह है कि कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी डीजेइंग शुरू करते हैं। जैसे, टीना वुड्स, जिन्हें डीजे टीना भी कहते हैं। उन्होंने ब्रिटेन में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हेल्थ इनोवेशन कंसल्टेंसी 'कोलाइडर हेल्थ' स्थापित की है। आज 62 की उम्र में टीना कहती हैं कि 'आंत्रप्रेन्योर होना बेहद अकेलेपन से भरा है और डीजे मुझे सामाजिक रूप से कनेक्ट रखता है।' ऐसे फाउंडर्स की सूची बहुत लंबी है, जो आज डीजेइंग कर रहे हैं या जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करने से पहले डीजेइंग शुरू की थी।

लेकिन यदि आप उनमें से हैं, जो दिनभर के कारोबार या हाई-प्रेशर जॉब के बाद घर जाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही शुरू करते हैं तो अगर आपको डीजेइंग असहज लगती है तो तनावमुक्त होने के लिए म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। फंडा यह है कि जीवन में या वर्कप्लेस पर अकेलेपन को मात देने के लिए आपको जरूर कोई तरीका खोजना चाहिए। किसी के साथ म्यूजिक सुनना भी एक थेरेपी है, जिसे आजमाया जा सकता है।एन. रघुरामन

राजनीतिक दलों और नेताओं के रिश्तों में खींचतान का दौर

बीते कुछ समय में शिवसेना के 6, तृणमूल के 20 और आप के 7 लोकसभा-राज्यसभा सांसद दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। तीनों ही मामलों में संबंधित दलों ने इन विलयों का विरोध किया था। इसके बावजूद, दल-बदल विरोधी कानून के तहत ये वैध माने जाते हैं। इसके पीछे कौन-सा तकनीकी पेंच है? दल-बदल विरोधी कानून को तो एक वास्तविक समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। सांसद और विधायक बार-बार दल बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते थे। हरियाणा के विधायक गया लाल ने तो एक ही दिन में तीन बार दल बदले थे। मंत्रिपद या अन्य लाभों के लालच में विधायकों को दल बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे निर्वाचित सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। 1967-68 के दौरान ही विभिन्न विधानसभाओं में दल बदलने वाले 210 विधायकों में से 116 को मंत्री बना दिया गया था। इस पर रोक लगाने के लिए 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत जनप्रतिनिधि जिस दल के टिकट पर निर्वाचित हुए हों, अगर वो उसे छोड़ते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका उद्देश्य स्पष्ट था- राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और मतदाताओं के जनादेश की रक्षा करना। हालांकि, इस कानून ने राजनीतिक दलों और चुने हुए प्रतिनिधियों के सम्बंधों की प्रकृति भी बदल दी। दसवीं अनुसूची से पहले विधायकों और सांसदों के पास अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी। वे अपने विवेक, जनहित या अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर सदन में मतदान कर सकते थे। लेकिन दल-बदल कानून ने शक्ति-संतुलन राजनीतिक दलों के पक्ष में कर दिया। यदि कोई सांसद या विधायक पार्टी-व्हिप का उल्लंघन करता या पार्टी की सदस्यता छोड़ता, तो उसे डिसक्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ सकता था। अर्थात् इस कानून के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर दलगत अनुशासन को प्राथमिकता दी गई। परंतु कानून ने कुछ अपवाद भी स्वीकार किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था राजनीतिक दलों का विलय। इस प्रावधान के अनुसार, यदि किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय हो जाए और उसे सदन में उस दल के दो-तिहाई सांसदों या विधायकों का समर्थन प्राप्त हो, तो ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्यता से संरक्षण मिलेगा। कानून की परिकल्पना यह थी कि विलय की प्रक्रिया में राजनीतिक दल और उसके निर्वाचित प्रतिनिधि-दोनों की भूमिका होगी। हालांकि समय के साथ न्यायालयों ने इस प्रावधान की ऐसी व्याख्या बनाई, जो दल-बदल कानून के व्यापक उद्देश्य से अलग दिखाई देती है। न्यायालयों ने दो-तिहाई बहुमत की शर्त को ही पर्याप्त मानना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप यदि किसी दल के पर्याप्त संख्या में सांसद या विधायक एक साथ किसी अन्य दल में जाने का निर्णय लेते हैं, तो दसवीं अनुसूची के उद्देश्य से उसे विलय मान लिया जाता है, भले ही मूल दल अस्तित्व में बना रहे और इसका विरोध करे। उदाहरण के लिए, आम आदमी पार्टी एक स्वतंत्र दल के रूप में मौजूद है, लेकिन उसके दस में से सात राज्यसभा सांसद अब भाजपा के साथ हैं। इसी प्रकार तृणमूल आज भी सक्रिय है और उसने अपने सांसदों के विलय का विरोध किया है। फिर भी वर्तमान कानूनी व्याख्या के अनुसार, यदि आवश्यक संख्या पूरी हो जाती है, तो दल की आपत्ति निर्णायक नहीं रहेगी। यह एक विचित्र विरोधाभास रचता है। इस तरह के विलयों के राजनीतिक परिणाम गंभीर होते हैं। वे सदन में बहुमत का संतुलन बदल सकते हैं, महत्वपूर्ण विधेयकों पर मतदान को प्रभावित कर सकते हैं और सरकारों की स्थिरता को भी संकट में डाल सकते हैं। यह समस्या छोटे राज्यों और क्षेत्रीय दलों के लिए अधिक गंभीर है, जहां विधायकों की संख्या सीमित होती है। छोटी विधानसभाओं में दो-तिहाई का आंकड़ा पाना आसान होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को महत्त्वपूर्ण माना गया था। इसीलिए यदि कोई सांसद या विधायक अपने दल के विरुद्ध जाता, तो अपनी सदस्यता खो सकता था। किंतु दल-विलय के प्रश्न में राजनीतिक दल की इच्छा को लगभग अप्रासंगिक बना दिया गया है। (ये लेखकों के अपने विचार हैं, अर्घ्य सेनगुप्ता और स्वप्निल त्रिपाठी)

क्या सिस्टम को तकनीक से जोड़ने भर से सब ठीक हो जाएगा?

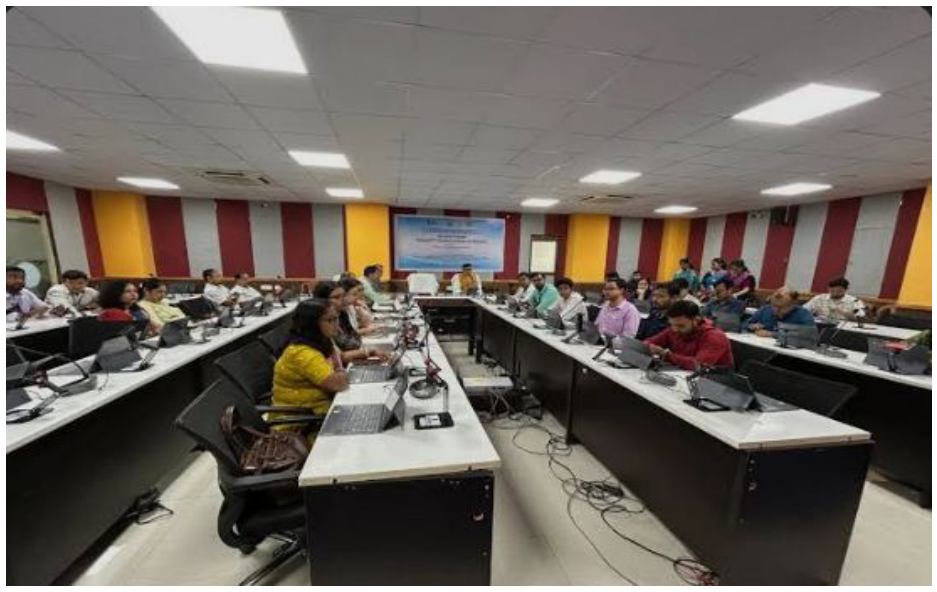

डिजिटल माध्यमों पर भरोसा करती दुनिया में नीट की भविष्य की परीक्षाओं का (21 जून को होने जा रही परीक्षा का नहीं) कम्प्यूटराइज्ड होना शुभ संकेत है और साथ-साथ सिस्टम और जनता के संबंधों पर उस भरोसे का भी मरहम है, जो कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन क्या सिस्टम को तकनीक से जोड़ने से सब ठीक हो जाएगा? क्या तकनीक भरोसे को बचा पाएगी? और फिर आइंदा लीक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी? शायद हां, शायद नहीं! नीट परीक्षा को लेकर अभी भी कितने पैरेंट्स और परीक्षार्थी संशय की स्थिति में होंगे। नागरिकों के लिए यह जानना आसान नहीं होता है कि सरकार में उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, हालांकि वे उनके काम-काज पर नजर बनाए रखते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को तो वोट की मदद से पद से हटाया जा सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी या सिविल सर्वेंट्स चुने हुए नहीं होते और इस तरह के नियंत्रण से सुरक्षित रहते हैं। तब नागरिकों को सरकारी एजेंसियों और उनके कर्मचारियों पर भरोसा रखना पड़ता है कि वे उनके हित में ही काम करेंगे। लेकिन यह सत्य है कि सिस्टम तो उनके भरोसे को बचा नहीं पा रहा है। पेपर लीक की घटना ने यह प्रश्न हम सभी के सामने रखा कि आखिर क्या किया जाए, जिससे यह दुबारा न हो? जब भी कोई ईमानदार व्यक्ति इस्तीफा देता है, तो शिकायत यही होती है कि व्यवस्था ईमानदारी का साथ नहीं देती और इसी वजह से व्यक्ति खुद को हमेशा अलग-थलग समझने लगता है, जबकि चारों ओर खामियां ही खामियां हैं।

तो क्यों नहीं इस सिस्टम को समझा जाए और यह भी खंगाला जाए कि इस सिस्टम को और सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है? इस संबंध में यह तर्क रहा है कि सरकारी अधिकारियों की सही भूमिका संरक्षक की होनी चाहिए, यानी एक प्रभावी और नैतिक प्रतिनिधि के तौर पर काम करके जनता का भरोसा जीतने की प्रशासक की इच्छा और उसकी क्षमता से लैस व्यक्तित्व। सिस्टम पर भरोसे को बचाए रखने के लिए सिर्फ एक कुशल और पेशेवर सिविल सर्वेंट होना ही नहीं काफी है, बल्कि न्याय और परोपकार के नैतिक मानदंडों से प्रेरित भी जरूरी है। हाल में यूपीएससी ने अपनी पीटी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे, जो मेन्स में पूछे जाने वाले एथिक्स के पेपर जैसे थे।

मानो पहले ही चरण में यूपीएससी अपने परीक्षार्थियों के नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को परखना चाह रहा था। क्योंकि सिस्टम उन नैतिक निर्णयों से ही उस भरोसे को बनाए रख पाता है, जो लोकतंत्र का आधार है।

तो क्या 21 जून को होने वाली नीट और अन्य परीक्षाएं त्रुटिरहित हो पाएंगी और किसी भी तरह के लीक से सुरक्षित रहेंगी? क्या सिस्टम भरोसे को कायम रख पाएगा? क्या भविष्य की कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा सिस्टम के नायकों की साख को और पारदर्शी बनाएगी? इसका उत्तर तो समय के ही पास है।

लेकिन यह तो निश्चित है कि सबकुछ संरक्षित करना, उस भरोसे को जीवित रखना अब इतना आसान नहीं होगा। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिन समाजों में आपसी विश्वास कम होता है, वहां नैतिक मूल्य साझा नहीं किए जाते और इसलिए नैतिक सहमति का अभाव होता है। ऐसे समाजों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोगों के सामाजिक-राजनीतिक विश्वास में लगातार आ रही गिरावट है। यदि राजनीति खुशी और एकता का माहौल बनाए, राजनीति को सेवा के एक माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाए और सिस्टम नैतिकता को बढ़ावा दे तो भरोसा एक बिल्कुल ही पारदर्शी रंग में नजर आएगा। सिस्टम में भरोसे को फिर से स्थापित करने के लिए तकनीक का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, साथ ही व्यवस्था को चलाने वाले नायकों को भी उस ईमानदारी या सत्यनिष्ठा को अपनाना होगा, जिससे वे खुद को नैतिक दुविधा से बाहर निकाल सकें। नीट की कम्प्यूटराइज्ड माध्यम से होने वाली परीक्षा और यूपीएससी की पीटी परीक्षा में नैतिक प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न उस भरोसे को निःसंदेह मजबूत बनाएंगे।

नैतिकता का लोकेशन परिधि में नहीं बल्कि केंद्र में होता है और सिस्टम इसी के गुरुत्व से चलता है। (ये लेखक के अपने विचार हैं,नंदितेश निलय)

चीन के विस्तारवादी मंसूबे अब हदें पार करने लगे हैं

विगत 2 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर निर्वासित तिब्बती कार्यकर्ता लोबगा रंगजेन द्वारा आत्मदाह कर लेना किसी व्यक्तिगत निराशा की अभिव्यक्ति नहीं थी। यह हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में से एक- तिब्बत को नष्ट किए जाने के प्रति दुनिया की बढ़ती उदासीनता को झकझोरने का एक हताश प्रयास था। पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना के तुरंत बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इसे अकसर मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, और इसके ठोस कारण भी हैं। लेकिन इसे एशिया की सबसे मूल्यवान भू-राजनीतिक संपत्तियों में से एक पर दावा जताने के प्रयास के रूप में भी समझा जाना चाहिए। विशाल और संसाधनों से समृद्ध तिब्बती पठार हिमालय की गोद में बसा है। इसमें एशिया की महान नदियों का उद्गम स्थल है। और यह दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के परिप्रेक्ष्य से सामरिक महत्व का स्थान है। हाल के दशकों में, चीन ने तिब्बत में भारी निवेश किया है। वहां पर व्यापक सैन्य बुनियादी ढांचे और विशाल बांधों का निर्माण किया है और रणनीतिक महत्व के खनिजों के खनन को भी स्थायी नियंत्रण चाहते हैं। शी ने निष्कर्ष निकाला है कि इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका वहां के लोगों की पहचान को मिटा देना है। तिब्बती लोग एक विशिष्ट जातीय समूह हैं, जिनकी अपनी भाषा, परंपराएं, भोजन और पोशाक हैं। तिब्बतियों से उनकी पहचान छीनना और यह सुनिश्चित करना कि वे अब खुद को तिब्बती न मानें- इसका एक ही लक्ष्य है : 'विश्व की छत' पर स्थायी चीनी शासन के विरुद्ध तमाम प्रतिरोधों को खत्म करना। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए चीन ने सरकारी छात्रावासों की प्रणाली का विस्तार किया है और तिब्बती बच्चों को कम उम्र में ही वहां भेजना शुरू कर दिया है। चीन इन आवासीय स्कूलों को विकास के इंजन बताता है। जबकि हकीकत यह है कि इनका पाठ्यक्रम बच्चों की तिब्बती पहचान को मिटाने और उसकी जगह चीन के प्रति निष्ठा पैदा करने के लिए बनाया गया है।संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि 6-18 वर्ष की आयु के दस लाख से अधिक तिब्बती बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्हें साल के अधिकांश समय अपने परिवारों और संस्कृति से अलग रखा जाता है, मंदारिन भाषा में पढ़ाया जाता है, हान संस्कृति के संपर्क में लाया जाता है और उन्हें अपनी ही संस्कृति, धर्म और भाषा को हीन समझने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, चीन तिब्बतियों की ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है, जो चीन में घुल-मिल जाए और अपनी संस्कृति भुला दे। तिब्बत को मिटाने के लिए चीन ने अन्य कदम भी उठाए हैं। 2023 के अंत से, चीन ने अपने सरकारी दस्तावेजों, राजनयिक संचार और मीडिया में तिब्बत के आधिकारिक नाम को बदलकर शिजांग कर दिया है। यह नाम तिब्बत के लिए मंचू किंग राजवंश की शब्दावली से लिया गया है। इसे अपनाना इस बात पर जोर देने के लिए है कि तिब्बत एक अलग ऐतिहासिक इकाई नहीं है, बल्कि चीन का एक अंग ही है। देखें तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी इन प्रयासों में मदद की ही है। चीन के बाहर कुछ संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों ने इस साम्राज्यवादी नाम-परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। पेरिस के एक संग्रहालय ने तिब्बती कलाकृतियों को शिजांग से आई हुई के रूप में लेबल किया है। ब्रिटिश संग्रहालय ने सिल्क रोड पर एक प्रदर्शनी में तिब्बत या शिजांग स्वायत्त क्षेत्र का उल्लेख किया है। अब तो चीन इस प्रयास को अगले स्तर पर ले जा रहा है। 1 जुलाई को जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला एक नया कानून लागू हो गया है, जो शी की उस मुहिम के अनुरूप है, जिसके तहत तिब्बतियों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी पर केंद्रित चीनी पहचान में घुलने-मिलने के लिए मजबूर किया जाएगा। जातीय एकता के लिए कथित खतरों को अपराध घोषित करके यह कानून एक और हथियार के रूप में तिब्बती कार्यकर्ताओं, विद्वानों और प्रवासी समुदायों को डराने-धमकाने का काम कर सकता है। चीन द्वारा दस लाख से भी अधिक तिब्बती बच्चों को मंदारिन भाषा में पढ़ाया जा रहा है, हान संस्कृति के संपर्क में लाया जा रहा है और उन्हें अपनी वास्तविक संस्कृति, धर्म और भाषा को हीन समझने के लिए तैयार किया जा रहा है। (प्रोजेक्ट सिंडिकेट,ब्रह्मा चेलानी)

नेपाली पीएम बालेन शाह ने अपना ही नियम क्यों तोड़ा! भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे, 3 महीने में ही फैसले से पलटे

काठमांडू।नेपाल सरकार ने पुष्टि की है कि भारत और चीन के राजदूतों के साथ अलग-अलग बैठकें इसी सप्ताह होंगी। हालांकि, दोनों बैठकों की सटीक तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की से या फिर ग्रुप मीटिंग के जरिए ही मिलेंगे। उनका मानना था कि विदेश नीति व्यक्तिगत मुलाकातों के बजाय सरकार और विदेश मंत्रालय के तय ढांचे के तहत चलनी चाहिए। उनका मानना था जब काठमांडू के मेयर थे, तब उन्होंने खुद को पारंपरिक नेताओं से अलग दिखाया था। इसी सोच के तहत उन्होंने नियम बनाया था कि वह किसी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे।

गई है। नेपाल का विदेश मंत्रालय इन बैठकों की अंतिम तैयारियों में जुटा है। बालेन शाह के पीएम बनने से पहले का नियम क्या था? नेपाल में नई सरकार बनने पर खासकर भारत, चीन और अमेरिका जैसे प्रभावशाली देशों के राजदूत सीधे प्रधानमंत्री के निजी आवास पर जाकर अलग-अलग मुलाकात करते थे। इन बैठकों में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद नहीं होते थे और न ही इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता था।नेपाल में लंबे समय से यह परंपरा रही थी कि बड़े देशों के राजदूत जब चाहें प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर लेते थे। इन मुलाकातों का मकसद अक्सर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने से ज्यादा व्यक्तिगत संपर्क मजबूत करना माना जाता था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हितों का टकराव पैदा होता था और नेपाल के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते थे। पीएम बनने के बाद बालेन शाह ने क्या बदलाव किए-बालेन शाह ने तय किया कि वह किसी भी विदेशी राजदूत या प्रतिनिधि से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक अलग 'रैंक प्रोटोकॉल' बनाया था। नए नियम के मुताबिक, वह सिर्फ किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष/प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री स्तर के अधिकारी से ही अकेले व्यक्तिगत बैठक करेंगे। निचले स्तर के अधिकारियों, राजदूतों या उप-मंत्रियों से वे अकेले मिलने के बजाय विदेश मंत्रालय के माध्यम कि कई शक्तिशाली देश सरकारी व्यवस्था को दरकिनार कर सीधे नेपाल के टॉप नेताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करते रहे हैं। इस फैसले के चलते बालने शाह ने कई बड़े विदेशी प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात करने से इनकार कर दिया। कई विदेशी अधिकारियों से नहीं मिले बालेन-भारत- बालेन शाह ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने से इनकार कर दिया। मिस्री प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बालेन शाह को भारत आने का औपचारिक न्योता देने काठमांडू आने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने के कारण उनका प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया। इससे भारत में नाराजगी भी देखी गई। अमेरिका- बालेन ने अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर और विशेष दूत सर्जियो गोर को भी अलग से मिलने का समय नहीं दिया। गोर नेपाल आने से पहले भूटान के प्रधानमंत्री और राजा तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके थे। चीन- बालेन ने चीन के उप वाणिज्य मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता यान डोंग से भी मुलाकात नहीं की। वह इसी महीने व्यापार और निवेश से जुड़े उच्चस्तरीय दौरे पर नेपाल आए थे। नोट- हालांकि इन घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये सभी घटनाओं की जानकारी रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दी गई हैं। बालेन शाह को अपना फैसला क्यों बदलना पड़ा-बालेन शाह लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ अलग छवि बनाना काफी नहीं है। देश चलाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सीधे बातचीत भी जरूरी होती है। इसी वजह से उन्होंने पहली बार अपना पुराना नियम तोड़ा है। भारत और चीन, दोनों नेपाल के सबसे अहम पड़ोसी हैं। ऐसे में दोनों देशों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखना उनकी सरकार की जरूरत बन गया है। नेपाल के लिए भारत और चीन दोनों क्यों जरूरी हैं? नेपाल की विदेश नीति हमेशा से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने पर आधारित रही है। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लाखों नेपाली नागरिक काम, व्यापार और पढ़ाई के लिए आसानी से भारत आते-जाते हैं। दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी होने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से भी जुड़े हैं। दूसरी ओर, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में सड़क, रेल, ऊर्जा और दूसरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसलिए नेपाल के लिए चीन भी एक अहम आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बन गया है।यही वजह है कि काठमांडू किसी एक देश के करीब दिखने के बजाय भारत और चीन, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है।

पैलेट्स से जख्मी इरशाद से नड्डा बोले-प्रोटेस्ट में क्यों गए, हॉस्पिटल ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी

नई दिल्ली।मैंने कहा- इरशाद ने बुलाया है। गार्ड ने जवाब दिया- नहीं बुलाया है। कुछ देर बार दी। मेरी बायीं आंख, चेहरे और कंधे पर गोली के छर्रे धंस गए। शरीर से खून बहने लगा। उस

बोला- रुकिए मैं पूछता हूं। इसी दौरान एक शख्स स्टाफ के साथ आए। वे खुद को गवर्नमेंट एम्पलाई बता रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा कि इरशाद से किसी को न मिलने दिया जाए। कुछ देर बाद इरशाद ने फोन पर कहा कि मैं अपने सवाल वॉट्सऐप पर भेज दूं। समझ नहीं आया कि इरशाद खुद मिलना चाहते थे, तब उनसे क्यों नहीं मिलवाया गया। ये अस्पताल प्रशासन का फैसला था या सुरक्षा एजेंसियों का या किसी और का, इसका जवाब नहीं मिला। मैं अस्पताल के बाहर इंतजार करती रही। कुछ देर बाद इरशाद का एक दोस्त बाहर आया। उसने दावा किया कि केंद्र सरकार में मंत्री जेपी नड्डा इरशाद से मिलने आए थे। उसी के बाद इरशाद के आसपास सख्ती बढ़ी है। कुछ देर बाद इरशाद का फोन आया। उन्होंने बताया कि अब मेरी हालत ठीक है। पढ़िए पूरी बातचीत- सवालः क्या आपको पैलेट गन से चोट लगी है? जवाबः हां। मेरे चेहरे और दाहिनी कंधे पर 40 से ज्यादा पैलेट्स लगे हैं। सवालः उस दिन क्या हुआ था? जवाबः मैं करीब 3:30 बजे कनॉट प्लेस पहुंचा। वहां से जंतर-मंतर की तरफ चला गया। उधर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे। अचानक उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम लोग पीछे की तरफ भागे। प्रदर्शन कर रहे सभी लोग नई उम्र के थे। तभी जवानों ने टियर गैस दागना शुरू कर दिया। सभी कनॉट प्लेस की तरफ आ गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं। हम यहां अपनी मांगें लेकर आए हैं। वे सभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नारा लगा रहे थे। मैंने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने अपनी गन हमारी तरफ तान दी। हमें लगा कि डराने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी फायर की आवाज सुनाई वक्त मैं होश में था। आसपास मौजूद लोगों ने खून रोकने की कोशिश की। एक स्कूटी रोककर मुझे लेडी हॉर्डिंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। सवालः क्या आपको मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है? जवाबः मैंने रिपोर्ट मांगी थी। बताया गया कि अभी इलाज और सर्जरी की प्रोसेस चल रही है। इसलिए फिलहाल पूरी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। डिस्चार्ज के वक्त रिपोर्ट दे देंगे। सवालः जेपी नड्डा आपसे मिलने आए थे, उनसे क्या बात हुई? जवाबः उन्होंने मेरा नाम-पता पूछा। फिर कहा कि मैं प्रदर्शन में क्यों शामिल था। मैंने उन्हें बताया कि मैं छोटे भाई-बहनों के भविष्य के लिए वहां गया था। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। सवालः क्या अभिजीत दीपके या उनके किसी साथी ने आपसे बात की है? जवाबः नहीं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। मेरा मकसद था कि हम अपनी आवाज उठा सकें और सरकार के सामने मांगें रख सकें। सवालः अपने साथ हुए हादसे पर क्या कहेंगे? जवाबः मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। इसके बाद भी मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं वहां गया। मैं यह सोचकर नहीं गया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। अगर फिर मौका मिला, तो मैं दोबारा वहां जाऊंगा। सवालः यानी आप खुद को इस आंदोलन का हिस्सा मानते हैं? जवाबः जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन का हिस्सा बना रहूंगा। सवालः आपने कहा था कि मैं आपकी दोस्त बनकर मिलने आ सकती हूं। डायरेक्टर के सामने आपने कहा कि मुझे जानते ही नहीं हैं। ऐसा क्यों? जवाबः नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था कि किसी को भी मुझसे मिलने न दिया जाए। मैंने कहा था कि कोई दोस्त आए तो मिल सकता है, लेकिन मुझे बताया गया था कि उसे फोन जमा कराना होगा। मेरा इलाज चल रहा है, इसलिए मुझे भी हॉस्पिटल के नियम मानने पड़ेंगे। सवालः आप नर्वस दिख रहे थे। क्या आपके ऊपर कोई सरकारी दबाव है? जवाबः कोई दबाव नहीं है। यहां मैं अकेला पेशेंट नहीं हूं। और भी मरीज हैं। उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। मुझे किसी ने डराया-धमकाया नहीं है। सवालः दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुई हैं। इस पर क्या कहेंगे? जवाबः मैं भी दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये उसी तरह की चीज है। अगर पैलेट गन इस्तेमाल होती है, तो उसके पार्टिकल्स बॉडी में घुस जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ है। दिल्ली पुलिस या फिर सरकार ने भले इसे नहीं माना, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैलेट गन हो सकती है। सवालः सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जवाबः अगर पैलेट गन पर बैन है, तो कैसे इस्तेमाल हो सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है। पैलेट गन का दावा सच निकला तो दिल्ली का पहला केस होगा-लेफ्ट के स्टूडेंट विंग आइसा के कार्यकर्ता दानिश के मुताबिक, रैपिड एक्शन फोर्स के वर्दीधारी जवान ने पैलेट गन से फायर किया गया था। अगर ये दावे सही हुए तो पहली बार होगा कि दिल्ली में सिविल प्रोटेस्ट में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन इस्तेमाल नहीं की गई है। ये दावे झूठे और भ्रामक हैं। इन अफवाहों को आगे न बढ़ाएं। पैलेट गन इस्तेमाल के नियम क्या हैं-पुलिस की तरफ से बल प्रयोग करने की स्टेप-बाय-स्टेप एसपी के मुताबिक पहले चेतावनी, फिर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, हल्का लाठीचार्ज और आखिर में नॉन-लीथल वेपन का इस्तेमाल। नॉन-लीथल वेपन, ऐसे कम घातक हथियार हैं, जो किसी व्यक्ति को अस्थायी तौर पर अक्षम कर देते हैं। जैसे- पैलेट गन और शॉक बैटन। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी की दंगा-रोधी इकाई आरएएफ के साजो-सामान में होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, नॉन-लीथल वेपन के तौर पर सुरक्षा बलों को पहले पावा ग्रेनेड (मिर्च के गोले), ग्रेनेड रोशनी-धमाके वाले गोले और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने चाहिए। फिर भी भीड़ न हटे तो पैलेट गन का इस्तेमाल करना चाहिए।

अमेरिका ने भारत पर 10फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, 60 देशों पर जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई

वॉशिंगटन डीसी। ऐसे में अतिरिक्त 10फीसदी टैरिफ से उन सेक्टरों पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जिनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अधिक है। इनमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर उत्पाद, कृषि एवं फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग इच्छा के खिलाफ काम कराया जाए। इसमें धमकी, कर्ज, हिंसा, दस्तावेज जब्त करना, वेतन रोकना या नौकरी छोड़ने की आजादी न देना जैसी परिस्थितियां शामिल होती हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानता है। अमेरिका का कहना है कि अगर किसी देश

आइटम शामिल हैं। अतिरिक्त टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे खरीदार दूसरे देशों के विकल्प तलाश सकते हैं या भारतीय निर्यातकों पर कीमत घटाने का दबाव बढ़ सकता है। भारत को 12.5फीसदी की जगह 10फीसदी टैरिफ क्यों मिला-शुरुआत में भारत पर 12.5फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। हालांकि बाद में भारत सरकार की ओर से श्रम मानकों और सप्लाई चेन की निगरानी से जुड़े कुछ नीतिगत सुधारों तथा अमेरिका के साथ लगातार बातचीत के बाद इसे घटाकर 10फीसदी कर दिया गया। फेडरल नोट में कहा गया है कि जून में प्रस्तावित टैरिफ घोषित होने के बाद भारत ने 14 जून को अपनी विदेशी व्यापार नीति में संशोधन किया। अमेरिका का मानना था कि भारत ने श्रमिक अधिकारों की निगरानी, नियमों के पालन और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर प्रस्तावित टैरिफ में 2.5फीसदी की राहत दी गई।10फीसदी टैरिफ लागू रहने का मतलब है कि भारत को पूरी छूट नहीं मिली है। यानी अमेरिका अब भी चाहता है कि भारत श्रम मानकों और फोर्स्ड लेबर से जुड़े नियमों को और प्रभावी ढंग से लागू करे। हालांकि 12.5फीसदी के बजाय 10फीसदी टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त लागत का बोझ कुछ कम होगा। फोर्स्ड लेबर क्या है, जिस पर अमेरिका सख्ती कर रहा है-फोर्स्ड लेबर का मतलब ऐसी मजदूरी से है, जिसमें किसी व्यक्ति से उसकी से आयात होने वाला सामान फोर्स्ड लेबर से जुड़ा पाया जाता है, तो उस पर अतिरिक्त टैरिफ या आयात प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य कंपनियों पर दबाव बनाना है कि उनकी सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल न हो।सेक्शन 301 क्या है, जिसके तहत अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया- सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट-1974 का एक प्रावधान है। इसके तहत अमेरिकी सरकार को यह अधिकार मिलता है कि अगर किसी देश की व्यापारिक नीतियां अमेरिकी कारोबार या उद्योगों के लिए अनुचित, भेदभावपूर्ण या नुकसानदायक मानी जाएं, तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस कार्रवाई में अतिरिक्त टैरिफ लगाना, आयात पर प्रतिबंध लगाना या दूसरे व्यापारिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। जांच की जिम्मेदारी अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) की होती है। जांच के दौरान संबंधित देश से जवाब मांगा जाता है और जरूरत पड़ने पर बातचीत भी की जाती है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी से कार्रवाई लागू होती है। पहले भी कई देशों और उद्योगों पर हो चुकी है कार्रवाई-अमेरिका पिछले कुछ वर्षों में फोर्स्ड लेबर के मुद्दे पर कई देशों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। खासतौर पर चीन के शिनजियांग क्षेत्र से आने वाले कॉटन, टमाटर, सोलर पैनल और उनसे जुड़े उत्पादों पर कड़े आयात प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा समुद्री खाद्य, पाम ऑयल, रबर, कोको, टेक्सटाइल और खनन जैसे उद्योग भी अमेरिकी जांच के दायरे में रहे हैं।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म, नड्डा ने जूस पिलाया, वांगचुक बोले- तीन मांगों पर लिखित आश्वासन मिला, इनमें प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं

गुरुग्राम। नीट पेपर लीक के खिलाफ 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वांगचुक ने शुक्रवार सुबह जारी वीडियो संदेश में कहा कि पिछले दो दिन से सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान उनकी तीन प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से इन मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। वांगचुक ने कहा- 'सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं करने, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने तथा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया।' वांगचुक ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उनके लिए सबसे अहम बात छात्रों पर कार्रवाई रुकवानी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना जरूरी नहीं था। वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। वांगचुक की 5 बड़ी बातें- 65 सांसदों का मिला समर्थनः विभिन्न दलों के करीब 65 सांसद उनसे मिले या उन्होंने संदेश भेजकर भरोसा दिलाया कि वे संसद में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली का मुद्दा उठाएंगे। दो दिन तक चली बातचीत के बाद बनी सहमतिः सरकार के साथ लिखित आश्वासन को लेकर लगातार दो दिन बातचीत हुई। इसी वजह से उन्होंने अनशन

दो दिन और जारी रखा और आखिरकार सहमति बनने पर इसे समाप्त किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं हुआः सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसे अनशन खत्म करने की अनिवार्य शर्त नहीं माना। आगे की लड़ाई के लिए जान बचाना जरूरीः उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अनशन जारी रखकर अपनी जान जोखिम में डालें या फिर आगे भी आंदोलन जारी रखने के लिए अनशन खत्म करें। हजारों लोगों की अपील के बाद उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकताः उनके लिए सबसे अहम मुद्दा यह था कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर कोई केस न हो। बाकी मुद्दों, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पर आगे भी दूसरे तरीकों से संघर्ष जारी रहेगा। मोदी बोले- वांगचुक डॉक्टरों का रूटीन फॉलो करें-पीएम मोदी ने रविवार रात एक्स पोस्ट कर कहा- मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। विपक्षी सांसदों ने भी मिलकर अनशन खत्म करने को कहा था-22 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचा, जहां सोनम वांगचुक भर्ती थे। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के विवेक तन्खा, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, सीपीआई(एम) के जॉन ब्रिटास, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई सांसद शामिल थे। सांसदों ने वांगचुक को एक संयुक्त पत्र सौंपकर अनशन समाप्त करने की अपील की और भरोसा दिया कि नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में मजबूती से उठाया जाएगा। शुरुआत में करीब 55 सांसदों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, बाद में यह संख्या बढ़कर लगभग 65 हो गई। वांगचुक ने 28 जून को भूख हड़ताल शुरू की थी-सोनम वांगचुक इस आंदोलन से 28 जून को जुड़े, जब उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट-यूजी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांगें थीं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट पेपर लीक और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार कर जवाबदेही तय की जाए और पेपर लीक से जुड़े छात्र आत्महत्या मामलों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। लद्दाख से जुड़ी मांग को लेकर भी अनशन कर चुके वांगचुक-यह सोनम वांगचुक का पहला अनशन नहीं था। इससे पहले उन्होंने मार्च 2024 में लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, पूर्ण राज्य का दर्जा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। इसके बाद सितंबर 2024 में वे 'दिल्ली चलो पदयात्रा' लेकर निकले, लेकिन दिल्ली सीमा पर हिरासत में ले लिए गए। 2025 में लद्दाख में आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद प्रशासन ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया था। बाद में मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने एनएसए के तहत उनकी नजरबंदी का आदेश वापस ले लिया और उन्हें रिहा कर दिया। अब उन्होंने नीट पेपर लीक और परीक्षा सुधार की मांग को लेकर 26 दिन तक अनशन किया, जिसे सरकार से तीन प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद समाप्त किया।

सीजेपी और सरकार के बीच फिर बातचीत,सीजेपी समर्थकों ने रात में बैरिकैड्स तोड़े

दीपके बोले- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन करेंगे

नयी दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरी बार बातचीत होगी। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। इसके बाद कल सरकार ने कहा कि हमने 4 बार सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया पर वे नहीं आए। वहीं, सीजेपी ने कहा था कि हम बात करने केंद्रीय मंत्री जेपी को देखते हुए आज सेंट्रल दिल्ली में राजीव चौक और लोक कल्याण मार्ग समेत 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। देर रात संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकैड्स तोड़े थे। सीजेपी ने आज देशभर में प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। सीजेपी बोली- सरकार दबाव में है, प्रधान इस्तीफा दें-कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका कहा- हम यह बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र पर यह फैसला लिया गया। इसके बाद सीपी पर न के बराबर लोग दिखे। मल्लिकार्जुन खड़गेः जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एकतरफा 'मन की बात' नहीं करनी होती। सोनिया गांधीः नरेंद्र मोदी सरकार ने छात्रों की हिम्मत का जवाब कायरता और क्रूरता से दिया है। सरकार उन्हें देश

जेपी नड्डा ने जितेंद्र को सीजेपी से बातचीत का जिम्मा

नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात हो। उधर, सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। नड्डा और जितेंद्र सिंह ने देर रात 12:30 बजे मेदांता अस्पताल जाकर उन्हें जूस पिलाया।सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार हमारे दबाव में है इसलिए पीएम को रात 12:30 बजे वीडियो जारी करना पड़ा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो जारी कर कहा था कि सरकार पेपर लीक पर कानून लाएगी। प्रदर्शन प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। रात 12:30 बजे प्रधानमंत्री को एक वीडियो जारी करना पड़ा, इसका मतलब है कि दबाव बहुत ज्यादा है। गुरुवार शाम 6:30 बजे से कनॉट प्लेस पर सभी दुकानें बंद-गुरुवार को न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया था। एसोसिएशन ने कहा था कि इलाके की गंभीर स्थिति को देखते हुए एनडीएमसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सलाह का भविष्य मानने के बजाय देश का दुश्मन समझ रही है।मोदी सरकार ने न सिर्फ भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिराया है, बल्कि मनमानी और संवेदनहीनता से काम करने की आदत भी बना ली है। राहुल गांधीः हमारे स्टूडेंट्स की मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। प्रधानमंत्री जी के वीडियो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तीन मांगें हैं- पहली, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा; दूसरी, 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को सजा; और तीसरी, छात्रों से माफी।

बेटी की आखिरी कॉल, बोली-मुझे बेच दिया-बचा लो, मोहाली में मां बोली-फिल्म शूट के बहाने ले गए

मोहाली। मां, मैं बहुत दुखी हालत में हूं- मनदीप कौर और उसके साथियों ने मुझे बेच दिया है। मुझे राजस्थान के गांव काकड़ा शिवपुरा में बंधक बनाकर रखा गया है। मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं किसी और के फोन से बात कर रही हूं-

यह बात मोहाली के कुंभड़ा गांव की रहने वाली 18 साल की वर्षा ने अपनी मां अंजू और सहेली को फोन पर कही थी। कॉल कटने के बाद से परिवार की सांसें अटकी हुई हैं। पति की मौत के बाद अब मां बेटी की तलाश में दर-दर भटक रही है। मां ने कहा कि पड़ोस में रहने वाली मनदीप कौर पंजाबी फिल्मों और गानों की शूटिंग में काम दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गई। 1 और 2 मई को वर्षा को फिल्म शूटिंग के नाम पर फिरोजपुर के गांव रत्ताखेड़ा ले जाया गया।शुरुआती दिनों में बेटी का परिवार से फोन पर संपर्क रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसका फोन बंद हो गया और वह लापता हो गई। इसके बाद से बेटी का पता नहीं चला। मां का आरोप है मनदीप कौर और उसके 4-5 साथियों ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर रखा है और वह अब यहां का मकान खाली कर दुबई भाग गई है। पिता की मौत हो चुकी, मां के साथ रहती थीः 23 जुलाई को थाना फेज-8 मोहाली में लड़की की मां अंजू (40) की शिकायत पर इंईं दर्ज हुई। जिसमें उन्होंने कहा कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले (तहसील हसनगंज, थाना अजगैनी) की रहने वाली हैं। वर्तमान में मोहाली के कुंभड़ा गांव में नीम वाले मंदिर के पास किराए के मकान में रहती हैं। उनके पति लच्छी राम की मौत हो चुकी है। परिवार की जिम्मेदारी अकेले उन पर है और वह मेहनत-मजदूरी करके घर चलाती हैं।

बारिश में फट रही एड़ियां-नमी, पानी, गंदगी है कारण,जानें कैसे सुरक्षित रखें, मानसून फुट केयर रूटीन के 8 स्टेप्स

नयी दिल्ली। बारिश का मौसम आते ही ज्यादातर लोग सर्दी-जुकाम, वायरल या डेंगू जैसी बीमारियों से बचने की बात करते हैं। लेकिन इसी मौसम में एक और समस्या परेशान करती है- एड़ियों का फटना। लोगों को लगता है कि एड़ियां सिर्फ सर्दियों में फटती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मानसून में लगातार गीलापन, गंदा पानी, खुले फुटवियर और पैरों की ठीक से देखभाल न करने की वजह से भी एड़ियां फट सकती हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो छोटी-सी दरार भी संक्रमण की वजह भी बन सकती है। इसलिए आज 'जरूरत की खबर' में जानेंगे कि मानसून में एड़ियां ज्यादा क्यों फटती हैं? किन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है? फटी एड़ियों से बचने के लिए क्या करें? विषय को समझेंगे एक्सपर्टः डॉ. विजय सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजी, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली जी के साथ सवाल जवाब के माध्यम से।

सवाल- क्या मानसून में एड़ियां ज्यादा फटती हैं?
जवाब- हां, ऐसा होता है। इस मौसम में पैर बार-बार गीले होते हैं। फिर सूखते हैं। बार-बार ऐसा होने के कारण त्वचा की बाहरी सुरक्षा परत (स्किन बैरियर) कमजोर होने लगती है। जब त्वचा अपनी नमी बनाए नहीं रख पाती तो एड़ियों की मोटी त्वचा सख्त होकर फटने लगती है। मानसून में बार-बार पैर गीले होने से त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो सकती है। अगर एड़ियां फटने के साथ खुजली, बदबू या दर्द भी हो तो तुरंत फंगल इन्फेक्शन की जांच करानी चाहिए।

सवाल- मानसून में ऐसा क्यों होता है?
जवाब- मानसून में एड़ियां ज्यादा फटने के पीछे कई कारण है। बार-बार पैर गीले होना। गीले जूते पहने रहना। त्वचा की नमी कम होना। खुले फुटवियर पहनना। कीचड़ गंदगी का संपर्क। पैरों की सफाई न करना। मॉइस्चराइजर न लगाना। फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ना।

सवाल- क्या पूमिक स्टोन से एड़ियां साफ करनी चाहिए?
जवाब- हां, लेकिन सही तरीके से। अगर एड़ियों में सिर्फ मोटी और सूखी त्वचा है तो नहाने के बाद प्यूमिक स्टोन से हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि-बहुत जोर से न रगड़ें। रोज इस्तेमाल न करें। खून निकल रहा हो तो बिल्कुल इस्तेमाल न करें। डायबिटीज के मरीज डॉक्टर की सलाह के बिना यूज न करें।

सवाल- क्या फटी एड़ियों में घरेलू नुस्खे भी कारगर होते हैं?
जवाब- कुछ घरेलू उपाय त्वचा को मुलायम रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये गहरी दरारों या संक्रमण का इलाज नहीं हैं। सीमित फायदा देने वाले कुछ घरेलू उपाय इस प्रकार हैं- नारियल तेल, पेट्रोलियम जेली, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, सवाल-कौन सी चीजें फटी एड़ियों पर कभी नहीं लगानी चाहिए?
जवाब- कुछ चीजें कभी न लगाएं। इनसे त्वचा और खराब हो सकती है, जैसेकि- नींबू (सीधे फटी एड़ियों पर लगाना) बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, गरम मोम (वैक्स) तेज ब्लेड से मृत त्वचा को काटनाः- सवाल- क्या पैरों को ज्यादा देर तक पानी में भिगोना सही है?
जवाब- नहीं। बहुत देर तक पैर पानी में रखने से त्वचा ज्यादा ड्राय हो सकती है। बेहतर है कि पैरों को- 5-10 मिनट तक गुनगुने पानी में रखें। उसके बाद अच्छी तरह सुखाएं। तुरंत फुट क्रीम लगाएं।

सवाल- मानसून में पैरों की डेली केयर कैसे करें?
जवाब- अगर रोज थोड़ी-सी सावधानी बरती जाए तो मानसून में भी एड़ियों को फटने से बचाया जा सकता है। उंगलियों को अच्छे से सुखाएं। रोज मॉइस्चराइजर लगाएं। रोज साफ मोजे पहनें। गीले मोजे तुरंत बदलें। एकदम सूखे जूते ही पहनें। बहुत टाइट फुटवियर न पहनें।

सवाल- कौन-सी गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं?
जवाब- अक्सर लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे एड़ियां और ज्यादा फट जाती हैं, जैसेकि- गीले जूते पूरे दिन पहनना। गंदे मोजे दोबारा पहनना। फटी त्वचा को खींचकर निकालना। ब्लेड से मृत त्वचा काटना। मॉइस्चराइजर न लगाना। दर्द होने पर भी अनदेखी करना। खुले घाव में घरेलू नुस्खे लगाना।

सवाल- कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
जवाब- अगर एड़ियों में सिर्फ सूखापन है तो घर पर देखभाल काफी होती है। लेकिन इन स्थितियों में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है-पैरों के ये संकेत इग्नोर न करें:-गहरी दरार पड़ना। खून निकलना। पस या पानी आना। तेज दर्द होना। चलने में दिक्कत होना। तेज खुजली होना। खराब स्मेल आता। हफ्तों तक सुधार न होना। डायबिटीज के मरीजों में घाव होना।

सवाल- मानसून में कैसा फुटवियर पहनना चाहिए?
जवाब- बारिश के मौसम में सही फुटवियर चुनना भी एड़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऐसा फुटवियर पहनें, जिसमें पैर लंबे समय तक गीले न रहें और फिसलने का खतरा भी कम हो।

क्या पहनें ? अच्छी ग्रिप वाले। जल्दी सूखने वाले। सही फिटिंग वाले। सांस लेने वाले यानी खुले। क्या न पहनें ? देर से सूखने वाले। बहुत टाइट और बंद। जिनमें हवा न जाए। जिनमें पानी आप ठीक हो जाती हैं? जवाब- अगर दरारें हल्की हैं और संक्रमण नहीं है, तो नियमित देखभाल से कुछ दिनों या हफ्तों में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर दरारें गहरी हों, दर्द या खून आने लगे या संक्रमण हो जाए, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

सवाल- डायबिटीज के मरीजों को क्या हो जाती है? जवाब- नहीं। अगर समस्या सिर्फ ड्राइ स्किन की है तो फुट क्रीम से लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन,एक्जिमा, सोरायसिस या कोई दूसरी बीमारी है, तो उसका अलग से इलाज करना पड़ता है। ऐसे में बिना सलाह के बार-बार अलग-अलग क्रीम लगाने से समस्या बढ़ भी सकती

खेसारी लाल यादव पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, फोटो के लिए कुत्ते को बेरहमी से घसीटा गया, एक्ट्रेस बोलीं- ये बेवकूफ आदमी है कौन, वाहियात

मुंबई। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर भड़क गई हैं। इतना ही नहीं एक्ट्रेस उन्हें पहचान भी नहीं सकीं और उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल, हाल ही में खेसारी लाल यादव एक इवेंट का हिस्सा बने थे। जैसे ही वो पोज देने के लिए कैमरामैन के सामने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जिस जगह बैकग्राउंड बैनर लगा है, ठीक उसी जगह एक आवारा कुत्ता बैठा है। खेसारी लाल यादव ने खुद तो कुत्ते को छुआ तक नहीं, लेकिन वहां मौजूद टीम ने उस कुत्ते को बेरहमी से घसीटते हुए वहां से अलग कर दिया। खेसारी लाल यादव शांत खड़े देखते रहे और कुत्ते को हटाए जाने के बाद उन्होंने वहां पोज दिए। इवेंट का वीडियो सामने आने के बाद मलाइका भड़क गईं। मलाइका ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से खेसारी लाल यादव का वो वीडियो शेयर कर भड़कते हुए लिखा है, 'ये लोग हैं कौन और ये आदमी कौन है, जो खड़ा होकर पोज दे रहा है। वाहियात।' इतना ही नहीं। ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो री-शेयर करने के अलावा मलाइका अरोड़ा ने शेयर किए गए वीडियो पर भी दो कमेंट किए। पहले कमेंट में मलाइका ने लिखा, 'वाहियात'। और दूसरे कमेंट में उन्होंने लिखा, 'ये बेवकूफ कौन है, क्या इसके लिए पोज देना इतना जरूरी था।' मलाइका का कमेंट सामने आने के बाद कई लोग खेसारी लाल यादव की पैरवी करते हुए उनकी पहचान बता रहे हैं। वहीं कुछ ट्रोलर्स ऐसे भी हैं, जो मलाइका को ही ट्रोल कर रहे हैं। कौन हैं खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म 'साजन चले ससुराल' (2011) सुपरहिट रही, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। खेसारी ने 100 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं। वे एक सफल अभिनेता होने के साथ-साथ लोकप्रिय गायक भी हैं। उनके कई गाने करोड़ों बार देखे और सुने जा चुके हैं। उन्होंने टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 13 में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। जिसे सलमान होस्ट करते हैं। खेसारी लाल यादव को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके अभिनय और गायन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। आज वे भोजपुरी मनोरंजन जगत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले और सबसे प्रभावशाली कलाकारों में गिने जाते हैं सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है।

पेपर लीक

कमल हासन बोले- सिस्टम सड़ चुका है, करीना बोलीं-छात्रों की बात सुनना अहसान नहीं हमारा फर्ज, इमरान और वरुण समेत कई एक्टर्स समर्थन में उतरे

मुंबई। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार आंदोलन को अब बॉलीवुड हस्तियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। सलमान खान, आलिया भट्ट और अनन्या पांडे के बाद अब करीना कपूर खान, कमल हासन, वरुण धवन, इमरान खान और पीयूष मिश्रा भी छात्रों के पक्ष में आ गए हैं। करीना कपूर ने कहा कि देश के युवाओं की मांग सुनना कोई अहसान नहीं, बल्कि हमारा फर्ज है। वहीं कमल हासन ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को सड़ा हुआ बताया है। इमरान खान ने मुंबई में खुद सड़क पर उतरकर छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। करीना बोलीं- बच्चे कल की तैयारी नहीं कर रहे, वे ही कल हैं करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मैं पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर शांत थी, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती। अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं की अनदेखी करना नामुमकिन है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। शिक्षा से बच्चे को भरोसा और उम्मीद मिलती है। लेकिन शिक्षा तभी काम करती है जब बच्चों को इस पर विश्वास हो। अगर उन्हें लगेगा कि ईमानदारी, मेहनत और मेरिट का कोई मतलब नहीं है, तो उनका भरोसा उठ जाएगा। करीना ने आगे लिखा, 'छात्रों को ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सकें। जब पूरी पीढ़ी अपने भविष्य के लिए एक आवाज में बोलती है, तो उन्हें सुनना अहसान नहीं, हमारा फर्ज है। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। वे कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे ही हमारा कल हैं।' कमल हासन बोले- सिस्टम सड़ चुका एक्टर और नेता कमल हासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, 'जब एक बच्चा रोया था, तब हमें सुन लेना चाहिए था। हमने तब तक इंतजार किया जब तक कई बच्चों की मौत नहीं हो गई। एक ऐसा सिस्टम जहां सीखने की जगह कोचिंग ने ले ली है, उत्सुकता की जगह चिंता ने ले ली है और मेरिट की जगह अपराध ने ले ली है, वह सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है। जब बच्चों को जवाबों की जगह बैरिकेड्स और लाठियां मिलती हैं, तो देश नाकाम साबित होता है। कमल हासन ने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने देश के बच्चों से कहा कि आपने अपना फर्ज निभाया है, अब देश को आपके लिए अपना फर्ज निभाना होगा। मुंबई में प्रदर्शन में शामिल हुए इमरान खान एक्टर इमरान खान बुधवार को नीट धांधली के खिलाफ मुंबई में आयोजित एक विरोध मार्च में खुद शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च के दौरान छात्रों पर हुए आंसू गैस और लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने लिखा था, 'जब मैंने देखा कि पुलिस छात्रों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज कर रही है, तो मेरा दिल टूट गया। जिन छात्रों ने मेहनत की, उन्हें सिस्टम ने धोखा दिया और जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाही तो उन्हें लाठियों से चुप करा दिया गया।' मुंबई मार्च के दौरान जब एक युवा कलाकार ने उनसे पूछा कि कई एक्टर्स राजनीति पर बोलने से बचते हैं, तो इमरान ने कहा, 'सच्ची कला में कलाकार का अपना नजरिया होता है। अगर आप अपनी राय के साथ खड़े नहीं हो सकते और अपनी कला में दिल नहीं डाल सकते, तो उस कला की कोई कीमत नहीं है।' वरुण धवन बोले- राजनीतिक फायदे के लिए न हो इस्तेमाल- एक्टर वरुण धवन ने भी इंस्टाग्राम पर छात्रों का समर्थन किया। वरुण ने लिखा, 'छात्र देश का भविष्य हैं। जब किसी छात्र का सपना टूटता है, तो सिर्फ एक सपना नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदें टूटती हैं। सिस्टम के फेल होने पर उन्हें सवाल पूछने का पूरा हक है। अधिकारियों को उनकी चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए और पारदर्शी हल निकालना चाहिए। यह केवल छात्रों का आंदोलन रहना चाहिए और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।' पीयूष मिश्रा ने कहा- इंकलाब जिंदाबाद-वहीं, सीनियर एक्टर और सिंगर पीयूष मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा दिया। पीयूष ने कहा, 'जंतर-मंतर पर जो कुछ भी हुआ, वह बहुत दुखद था। मैं छात्रों के साथ हूं। पुलिस और बच्चों को चोट पहुंची, यह सब गलत था। अगर सरकार और प्रशासन पहले ही छात्रों की बात सुन लेता, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।'

स्वत्वाधिकारी
एवं मुद्रक
डॉ. दीपक अरोरा
द्वारा रामा प्रिंटर्स
53/25/1 ए बेली रोड
न्यू कटरा प्रयागराज
(उ.प्र) 211002 से
मुद्रित एवं सी-41यूपी
एसआईडीसी औद्योगिक
क्षेत्र नैनी प्रयागराज।
संपादक/प्रकाशक
डा.पुनीत अरोरा
मो.न.09415608710
RNINO.UPHIN/2015/63398
www.adhuniksamachar.com

नोटः- इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी0आर0बी0 एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होगा।